page 1 and 8 Apr 2_page 1 Mar 25 final ds.qxd 4/2/2026 1:45 AM Page 1

epaper.dehatsandesh.com

3 सांसद गुलाम अली खटाना ने उठाया जम्मू-कश्मीर में शिक्षा योजनाओं का मुद्दा

5 टेबल टेनिस वर्ल्ड कप में मनिका ने नाकआउट की उम्मीदें जिंदा रखीं

8 कद्दूवर्गीय सब्जियों में - समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन

मौसम जम्मू — न्यूनतम 21 — अधिकतम 31

E-mail: dehatsandesh@gmail.com

जम्मू-कश्मीर का एकमात्र ग्रामीण दैनिक

देहात संदेश

वर्ष-23, जम्मू तवी, अंक-80 | जम्मू तवी, वीरवार 02 अप्रैल, 2026 | मूल्य-3 रूपये- (लेह) 4 रूपये | पृष्ठ -8

पश्चिम एशिया संकट पर सीसीएस की बैठक

आम लोगों पर असर कम करने के लिए व्यापक उपायों की समीक्षा

नई दिल्ली, 01 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की विशेष बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कीमतों की स्थिरता और विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उपायों की समीक्षा की गई।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में कृषि, उर्वरक, शिपिंग, विमानन, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों पर चर्चा हुई। पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर एलपीजी और एलएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्रोतों के विविधीकरण पर जोर दिया गया, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी कीमतों को स्थिर बनाए रखने

और जमाखोरी-कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की जानकारी दी गई।

सरकार ने बताया कि पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शनों के विस्तार, गैस आधारित बिजली संयंत्रों को राहत, और तापीय बिजली संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं, ताकि गर्मियों में बिजली की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। सरकार के अनुसार, आने वाले महीनों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है।

उर्वरक आपूर्ति को लेकर यूरिया उत्पादन बनाए रखने और डीएपी/एनपीकेएस के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ समन्वय किया जा रहा है। राज्यों को उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई तेज करने को कहा गया है।

खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमतें पिछले एक महीने में स्थिर बनी हुई हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और कीमतों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ निरंतर संपर्क में हैं।

बैठक में ऊर्जा, उर्वरक और अन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं के वैश्विक स्रोतों के विविधीकरण, हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और कूटनीतिक प्रयासों पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया और खरीफ तथा रबी सीजन के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्राथमिक लक्ष्य इस वैश्विक संकट के प्रभाव से नागरिकों को सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया कि गलत सूचना और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक सही और समय पर जानकारी का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वे प्रभावित क्षेत्रों और नागरिकों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएं।

सीमावर्ती गांव मकवाल का उपराज्यपाल का दौरा

किसी भी परिवार को छूटने न दिया जाए और किसी भी वास्तविक आवश्यकता को नजरअंदाज न किया जाए : सिन्हा

जम्मू, 01 अप्रैल। सीमावर्ती गांव भारत की पहली रक्षा पंक्ति हैं और यहां के निवासी किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए भारत का पहला चेहरा होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग साहस, त्याग और धैर्य में अग्रणी हैं और आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी की प्राथमिकताओं में भी सबसे आगे हैं, यह बात उपराज्यपाल Manoj Sinha ने बुधवार को कही। उपराज्यपाल ने कहा कि सीमावर्ती गांवों के निवासी हर दिन राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर परिवार के जीवन स्तर में स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। उपराज्यपाल जम्मू के सीमावर्ती गांव मकवाल में Vibrant Villages Programme के दूसरे चरण के तहत आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी परिवार छूटना नहीं चाहिए और किसी भी वास्तविक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जहां

उपराज्यपाल सिन्हा ने पांच निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का दिया आदेश

जम्मू, 01 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज पांच निरीक्षकों (मंत्रालयी) को तत्काल प्रभाव से पुलिस उप अधीक्षक (मंत्रालयी) के पद पर पदोन्नत करने का आदेश दिया। सरकारी आदेश संख्या 187-गृह, 2026 के अनुसार निरीक्षकों (मंत्रालयी) को वेतनमान में पुलिस उप अधीक्षक (मंत्रालयी) के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करने की स्वीकृति दी जाती है। पदोन्नत अधिकारियों में फिदा हुसैन शेख, फारूक अहमद नाइकू, मोहम्मद फारूक मीर, मंजूर हुसैन और अब्दुल राशिद मीर शामिल हैं। आदेश में कहा गया है कि पदोन्नतियां वेतन स्तर-8 में की गई हैं और किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन होंगी।

मौजूदा योजनाएं मकवाल और अन्य सीमावर्ती गांवों में कम पड़ रही हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर समाधान तैयार किए जाने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए सीमावर्ती गांवों का विकास एक भावना, संकल्प और जिम्मेदारी है। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार के वादों और लोगों को मिलने वाले वास्तविक लाभ के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा, किसी भी योजना की योजना बनाते या उसे लागू करते समय हमेशा यह याद रखें कि मकवाल और अन्य सीमावर्ती गांवों का हर परिवार सिर्फ सीमा पर नहीं रह रहा, बल्कि भारत की सुरक्षा में प्रहरी के रूप में खड़ा है।उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि सीमावर्ती गांव देश का अंतिम नहीं, बल्कि पहला गांव होते हैं। यहां रहना, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पण के साथ एक समृद्ध समाज का निर्माण करना असाधारण साहस का कार्य है।

कृषि परिवर्तन के लिए SKUAST-जम्मू और IFPRI सहयोग पर उपराज्यपाल की उच्चस्तरीय बैठक

जम्मू, 01 अप्रैल। उपराज्यपाल ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें SKUAST-Jammu और International Food Policy Research Institute के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की गई। इस सहयोग का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण और सतत कृषि परिवर्तन को मजबूत करना है।

बैठक में मुख्य सचिव अतल डुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि उत्पादन) डॉ. आशीष चंद्र वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) शैलेन्द्र कुमार, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप के. भंडारी, कुलपति प्रो. बी. एन. त्रिपाठी, आईएफपीआरआई-दक्षिण एशिया के निदेशक डॉ. शाहिदुर राशिद, वरिष्ठ शोध फेलो डॉ. अंजनी कुमार, मिशन निदेशक (एचएडीपी) डॉ. सागर डोइफोडे दत्तात्रेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और संकाय सदस्य उपस्थित थे। उपराज्यपाल ने IFPRI के साथ प्रस्तावित सहयोग का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी वैश्विक विशेषज्ञता क्षेत्र में संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

बैठक में SKUAST-Jammu में IFPRI के सहयोग से फूड पॉलिसी और डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) स्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह केंद्र एक ज्ञान हब के रूप में कार्य करेगा, जो सतत निगरानी, नीतियों के मूल्यांकन और डेटा-आधारित निर्णय लेने में सहायता करेगा। साथ ही, यह विशेष रूप से पर्वतीय और उच्च मूल्य उत्पादन प्रणालियों में कृषि परिवर्तन पर राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर विचार-विमर्श में भी योगदान देगा।

बैठक के दौरान IFPRI के विशेषज्ञों, जिनमें डॉ. शाहिदुर राशिद और डॉ. अंजनी कुमार शामिल थे, ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक संस्थागत और तकनीकी सहयोग पर अपने विचार साझा किए। डॉ. अंजनी कुमार ने जम्मू-कश्मीर में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के पुनरोद्धार के लिए संस्थागत और तकनीकी समर्थन विषय पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

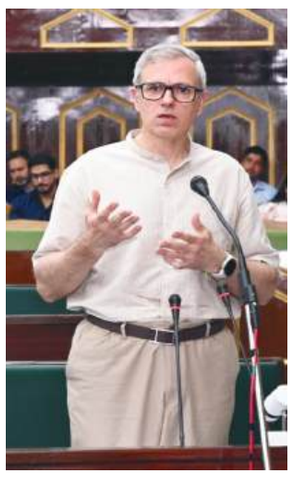

दैनिक वेतन भोगियों के चरणबद्ध नियमितीकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध: उमर

जम्मू, 01 अप्रैल । जम्मू और कश्मीर में दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज विधानसभा को सूचित किया कि चालू वित्त वर्ष में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी। उन्होंने विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए ये टिप्पणी की, जिसका शीर्षक था, जम्मू और कश्मीर सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत आकस्मिक और अन्य श्रमिकों की सेवाओं के नियमितीकरण और उससे संबंधित मामलों के लिए विधेयक (विधायी विधानसभा निजी सदस्य विधेयक संख्या 45, 2025)। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे नियमितीकरण संबंधी प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य का विरोध नहीं करते लेकिन इसके प्रस्तुत किए जाने के समय को लेकर उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट प्रतिबद्धता जता चुकी है कि चालू वित्त वर्ष में नियमितीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी और हम उस प्रतिबद्धता पर कायम हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विरोध विधेयक की भावना के विरुद्ध नहीं बल्कि इस समय इसे पेश किए जाने के विरुद्ध है, विशेषकर तब जब सरकार ने हाल ही में इस विषय पर घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रतिबद्धता किए हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता है। मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन इस मुद्दे को उठाना निरर्थक प्रतीत होता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार उन कर्मचारियों की चिंताओं को पूरी तरह समझती है जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष सेवा में समर्पित किए हैं और पुष्टि की कि उनका नियमितीकरण उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि मामला वर्तमान में एक समिति द्वारा जांच के अधीन है और उसकी रिपोर्ट का इंतजार करने का आग्रह किया। उन्होंने विधायक तारिगामी से सरकार के आश्वासन और चल रही प्रक्रिया को देखते हुए निजी सदस्य विधेयक वापस लेने की अपील की। बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासनों से संतुष्ट होकर विधायक मुहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपना विधेयक वापस ले लिया। इसी विषय पर विधायक वहीदउर रहमान पारा द्वारा पेश किया गया एक अन्य विधेयक जिसका शीर्षक था तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी, आवश्यकता आधारित और अन्य अस्थायी श्रमिकों के नियमितीकरण के लिए एक विधेयक (विधायक विधायक का निजी सदस्य विधेयक संख्या 8, 2025), ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया।

विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भूमि अनुदान विधेयक पर एनसी की कड़ी आलोचना की

जम्मू 01 अप्रैल । विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने बुधवार को एनसी पर जनता के जनादेश का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा भूमि अनुदान अधिनियम में संशोधन हेतु निजी सदस्य विधेयक को मंजूरी देना सार्वजनिक संपत्तियों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है। विपक्ष के नेता शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने एनसी को यह विश्वास दिलाकर वोट दिया था कि वह उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी, वे अब निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद है- ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जनादेश अब जनता के हित में नहीं, बल्कि अभिजात वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है—चाहे वह नेडौस हो, मुख्यमंत्री की निजी संपत्ति हो, या प्रभावशाली लोगों का समूह हो।

प्रस्तावित विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि अनुदान अधिनियम में संशोधन शीर्षक से एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया गया और मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी देने में जरा भी देर नहीं की। इससे गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा लगता है कि यह कदम सरकारी जमीनों के विशाल भूभागों को कम दामों पर दोबारा पट्टे पर देने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जो दशकों से चली आ रही एक परंपरा को जारी रखेगा।

उन्होंने पूछा कि इससे आम नागरिक को क्या संदेश मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने और हाशिए पर पड़े लोगों को न्याय दिलाने के बजाय, सरकार कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को बढ़ावा दे रही है और उनका संरक्षण कर रही है—वे लोग जो लंबे समय से गरीबों की कीमत पर लाभ उठाते रहे हैं। यह न केवल निराशाजनक है, बल्कि विश्वासघात है।

पैरामेडिकल स्टाफ की 2.5 दिन की सैलरी बहाल होगी

जम्मू, 01 अप्रैल । स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने कहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ की 2.5 दिन की रोकी गई सैलरी को समिति की रिपोर्ट के बाद बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है और इस मामले में सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि रिपोर्ट आने के बाद कर्मचारियों की लंबित मांगों पर उचित कदम उठाए जाएंगे।

कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सुरक्षा कुंजी, धार्मिक स्थलों पर सरकार का ध्यान- मुख्यमंत्री उमर

जम्मू, 01 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी एक सुरक्षित वातावरण की बहाली पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सरकार उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगी।

एक निजी विधेयक पर चर्चा के दौरान विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन एक वास्तविकता है जिससे न तो सरकार इनकार करती है और न ही कोई। उन्होंने कहा कि लगातार सरकारों ने उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के प्रयास किए हैं लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां समुदाय के सदस्य वापस आने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि समुदाय की सुरक्षा की भावना गहराई से प्रभावित हुई है और किसी भी सार्थक वापसी से पहले इसका पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। उस विश्वास को बहाल किए बिना उनकी वापसी की उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं होगा।

अधिकारियों की अनुपस्थिति के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा सदस्य एकजुट, स्पीकर ने मामला मुख्यमंत्री को भेजा

जम्मू, 1 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को एक दुर्लभ सर्वसम्मति देखी गई जब सभी दलों के सदस्य गैलरी से वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज हो गए जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को इस मुद्दे को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सामने रखना पड़ा। प्रश्नकाल के अंत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने यह मुद्दा उठाया जिसका सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों ने समर्थन किया जो विरोध में अपनी सीटों से खड़े हो गए। स्पीकर ने विरोध कर रहे सदस्यों को आश्वासन दिया कि सदन ने उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया है। इस बात पर जोर दिया कि जब भी उनके विभागों से संबंधित प्रश्न उठाए जाएं तो संबंधित अधिकारियों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। राथर ने कहा कि स्थान की कमी को देखते हुए पूरे सचिवालय का यहां उपस्थित रहना न तो उचित है और न ही संभव है।

हालांकि मुख्यमंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब ऐसे प्रश्न उठाए जाएं तो संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें और वे उचित नोट्स लें और सदस्यों की चिंताओं को उनकी संतुष्टि के अनुसार संबोधित करें।

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कहा कि अधिकारियों की अनुपस्थिति सही प्रथा नहीं है।

डिविजनल कमिश्नर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 की तैयारियों की समीक्षा की

श्रीनगर, 01 अप्रैल। वार्षिक Shri Amarnath Ji Yatra (SANJY) 2026 के सुचारू और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए, कश्मीर के मंडलायुक्त Anshul Garg ने बुधवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पवित्र गुफा की यात्रा के लिए तैयारियों का आकलन किया गया और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में अनंतनाग, बडगाम, गांदरबल, बांदीपोरा और श्रीनगर के उपायुक्तों के साथ-साथ श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इनमें यूएलबी, एफसीएस एंड सीए, आरटीसी, आरटीओ, ग्रामीण स्वच्छता, Shri Amarnath Shrine Board, केपीडीसीएल, आर एंड बी, पीएचई, आई एंड एफ, आयुष, बीकन, पशुपालन, श्रम, स्वास्थ्य, सूचना, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आईएमडी, पर्यटन, एसडीए, पीडीए, वन, वन्यजीव, एसडीआरएफ, जिला एसएसपी, आईटीबीपी, एनएचआईडीसीएल और एनएचएआई शामिल थे।

तेल टैंकर में अचानक लगी भीषण आग

जम्मू, 01 अप्रैल। जम्मू के नरवाल इलाके से बुधवार को एक भयानक घटना सामने आई है जहां एक तेल टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई।

आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा टैंकर धू-धू कर जलने लगा जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें काफी ऊंचाई तक उठ रही थीं और काला धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था।

घटना ट्रांसपोर्ट नगर/आरटीओ के नजदीक हुई जो एक व्यस्त इलाका माना जाता है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम तेजी से शुरू किया गया।

रेलवे ने इस साल 1670 मिलियन टन माल ढुलाई का बनाया रिकॉर्ड : वैष्णव

नई दिल्ली, 01 अप्रैल । रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारतीय रेल ने वर्ष 2025-26 के दौरान माल ढुलाई में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए 1670 मिलियन टन (एमटी) कार्गो का परिवहन किया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और देश की लॉजिस्टिक्स प्रणाली में रेल की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में रेलवे के विकास के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन किया है, उसका लाभ भी बहुत मिला है। जैसा कि रेलवे गरीबों और मध्यम वर्ग की सवारी है। पिछले एक दशक में जो निवेश हुआ है उसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति और मध्यम वर्ग परिवारों को हुआ है। उन्होंने कहा कि हाल ही में समाप्त हुए वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने 76,352 विशेष ट्रेनें चलाईं हैं। वर्तमान

में रेलवे नेटवर्क पर प्रतिदिन लगभग 25,000 ट्रेनें चलती हैं। रेलवे ने इस वर्ष के दौरान 1,670 मिलियन मीट्रिक टन माल परिवहन का रिकॉर्ड हासिल किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 50 साल के इतिहास में इस वर्ष सबसे कम संख्या में गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। केवल 16 गंभीर दुर्घटनाओं की सूचना मिली, जो सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

गांदरबल में रातभर चली मुठभेड़, एक आतंकवादी मारा गया

श्रीनगर, 01 अप्रैल । सेना ने बुधवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में रात भर चली मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षाबलों ने मंगलवार रात गांदरबल जिले के अरहामा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया।

श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने एक्स पोस्ट में बताया कि विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गांदरबल के अरहामा क्षेत्र में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। सेना ने कहा कि तलाशी के दौरान सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। चुनौती मिलने पर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और हमारे सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई की। सेना ने लिखा कि रुक-रुक कर हो रही गोलीबारी के बीच घेराबंदी को रणनीतिक रूप से पुनर्गठित किया गया और सैनिकों ने सुनियोजित जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है।

भूमि अनुदान अधिनियम में संशोधन का विधेयक कश्मीर के अति-अमीर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है: सज्जाद लोन

जम्मू, 01 अप्रैल । पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने बुधवार को कहा कि भूमि अनुदान अधिनियम में संशोधन का विधेयक कश्मीर के अति-अमीर वर्ग को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है।

लोन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह विधेयक कश्मीर के अति-अमीर वर्ग की मदद करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने निजी सदस्य विधेयक पेश करने की अनुमति दी। सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। यह विधेयक भूमि से संबंधित है - विशेष रूप से सरकारी जमीनों पर समाप्त हो चुके पट्टों के विस्तार से। इसमें कश्मीर की कुछ सबसे महंगी अचल संपत्तियां शामिल हैं जिनकी कीमत, मेरा अनुमान है लगभग 70,000 से एक लाख करोड़ रुपये या शायद इससे भी कहीं अधिक है।लोन की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री द्वारा विधेयक का विरोध न करने की घोषणा के कुछ ही मिनट बाद आई।

उन्होंने सवाल उठाया कि इस विधेयक में समाज के

सबसे गरीब तबके के लिए क्या प्रावधान हैं। उन्होंने पूछा कि लाखों गरीब परिवारों ने 2 या 3 मरला या ज़्यादा से ज़्यादा एक कनाल ज़मीन पर घर बनाए हैं। उन्हें रोज़ाना उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। वे दशकों से जितने असहाय रहे हैं आज भी उतने ही असहाय हैं। क्या उन्हें इस विधेयक का हक नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विधेयक के विरोध में नहीं हैं लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे सिर्फ़ अति-अमीर वर्ग को ही फ़ायदा होगा।

गर्भावस्था

छोटी-छोटी बातों का रखें ख्याल

गर्भावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें महिला को न सिर्फ अपना, बल्कि अपने होने वाले शिशु के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होता है। गर्भावस्था का परिणाम एक स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु होना चाहिए। गर्भावस्था में उचित खुराक, आराम, व्यायाम, चिकित्सकीय देखभाल, जांचों और जरूरत पड़ने पर कुछ दवाओं की जरूरत होती है। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है।

गर्भावस्था के प्रारंभिक तीन महीनों में कई महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस या जी मचलाने या मितली आने की शिकायत होती है। इस अवधि में सुबह बिस्तर से निकलने से पहले ही सूखा बिस्किट खा लें। थोड़ी बहुत चाय-कॉफी और हल्का खाना, फल, सलाद खाते रहें। बच्चे के समुचित विकास के लिए मां की खुराक में ज्यादा कैलोरी, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम आवश्यक है।

आमतौर पर भारतीय शाकाहारी होते हैं। इसलिए खुराक में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए दालों और अंकुरित अनाज भी खाना आवश्यक है। यदि चार-पांच प्रकार की दालें मिलाकर बनाएं तो और अच्छा है। इनके अलावा मूंगफली, छोले, राजमा, भुने चने और हो सके तो सूखे मेवे का नियमित सेवन करना चाहिए। सोयाबीन भी प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है।

महिलाओं में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होना भी बहुत अधिक पाया जाता है। इससे बचने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद खाना आवश्यक है। आयरन की गोली अवश्य लें। विटामिन-सी के सेवन से आयरन का अच्छी तरह से अवशोषण होता है। कैल्शियम के लिए आहार में रोज प्रचुर मात्रा में दूध, दही या मट्ठा होना चाहिए। कमी अधिक हो तो कैल्शियम की गोली भी लेना चाहिए।

हर गर्भवती महिला को रात में कम से कम आठ घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। साथ ही दिन में भी एक-दो घंटा आराम की जरूरत है। गर्भावस्था में रोजमर्रा का हल्का-फुल्का काम किया जा सकता है, लेकिन भारी काम से पूरी तरह परहेज करें। साथ ही उचित व्यायाम करना आवश्यक है। गर्भावस्था के व्यायाम की जानकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ से ले सकते हैं। विशेषज्ञ से सलाह लिए बगैर मन से व्यायाम न करें। बेहतर होगा कि व्यायाम योग्य प्रशिक्षक की मौजूदगी में करें।

भ्रांतियों से दूरी बनाएं

कई घरों में यह मान्यता होती है कि गर्भावस्था के सातवें-आठवें महीने तक डॉक्टरी जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जो सरासर गलत है। मासिक धर्म रुकने के तुरंत बाद ही डॉक्टरी जांच करवाकर निश्चित करवाएं की आप गर्भवती हैं। पहले छह महीने तक एक-एक महीने के अंतराल से जांच करवाना चाहिए। सातवें महीने से हर पंद्रह दिन में जांच करवाएं। नवां महीने लगने पर हर हफ्ते जांच की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर कम से कम दस बार जांच होना चाहिए।

चिकित्सक की सलाह मानें

डॉक्टर की सलाह के अनुसार परीक्षण और आवश्यकतानुसार सोनोग्राफी होना चाहिए। पहली सोनोग्राफी जांच ड़ेढ़-दो महीने की गर्भावस्था में ही की जाती है। इससे भ्रूण की स्थिति के सही निदान के साथ ही प्रसव की सही तारीख भी तय की जा सकती है। इसके बाद चौथे महीने में यानी कि सोलह से अठारह हफ्ते में सोनोग्राफी करवाकर गर्भस्थ भ्रूण के अंदर कोई जन्मजात गड़बड़ी जैसे कि हृदय, सिर में, रीढ़ में या पेट में गड़बड़ी हो तो उन्हें देख लिया जाता है।

तिम तिमाही में रहें सावधान

सातवें-आठवें महीने में सोनोग्राफी से गर्भनाल की स्थिति, शिशु का वजन, बच्चेदानी के अंदर का पानी सभी की जांच होती है। आपके डॉक्टर को जरूरत पड़ने पर सातवें महीने के बाद एक से अधिक सोनोग्राफी की जरूरत हो सकती है।

भ्रूण का विकास कम हो तो क्या करें

यदि बच्चे में विकास की दर कम हो तो पहले यह सुनिश्चित करें कि मां गर्भावस्था के दौरान कोई बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर (रक्त चाप), डायबिटीज (मधुमेह) से तो पीड़ित नहीं थी। यदि वह बीमार है तो कलर डॉप्लर सोनोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। इसमें शिशु के धमनियों में रक्त का प्रवाह कैसा है, इसे जांचा जाता है और आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है।

न कराएं लिंग परीक्षण

ध्यान रहे कभी भी शिशु का लिंग परीक्षण करवाने के लिए सोनोग्राफी न करवाएं। यह न केवल आपके और समाज के लिए हानिकारक है वरन्? कानूनन अपराध भी है। प्रसूति विशेषज्ञ द्वारा नियमित रूप से आपकी खून की एवं पेशाब की जांचें करवाई जाएंगी। हिमोग्लोबिन की जांच गर्भावस्था में तीन-चार बार करवाना आवश्यक है। आपका रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) जानना जरूरी है। यह भी तय करें कि आप आर.एच. निगेटिव तो नहीं हैं। सातवें महीने में ग्लूकोज देकर शुगर की जांच होती है। पेशाब की जांच से यूरिनरी इंफेक्शन का पता चलता है। इन सबके अलावा एचआईव्ही और हिपेटाइटिस बी की जांच करवा लेना चाहिए।

टिटेनस के टीके

गर्भावस्था में महिला को टिटेनस टॉक्साइड के दो इंजेक्शन चार से छह हफ्ते के अंतराल से लगते हैं, जिनसे मां और नवजात शिशु दोनों में टिटेनस की रोकथाम होती है। जिन महिलाओं की गर्भावस्था सामान्य रहती है, उनको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन कई बार गर्भावस्था हाई-रिस्क या असामान्य श्रेणी में आती है।

क्या आपका बच्चा पूरी रात आराम से सोता है? कई बार माताएं शिकायत करती हैं कि उनका बच्चा पूरी रात ठीक से नहीं सोता, जिस वजह से उन्हें भी रातभर जाग कर शिशु की देखभाल करनी पड़ती है। पहले तो दिनभर के काम निपटाओ और फिर जब रात को सोने की बारी आती है तो बच्चा सोने नहीं देता। ऐसी ही समस्या का समाधान आज हम यहां पर देगें, जिससे आपका बच्चा आराम से रात को सो सकेगा और आप भी चैन की नींद लेंगी।

क्या आपका बच्चा रातभर आराम से सोता है?

इन तरीकों से सुलाएं अपने बच्चे को

अच्छी तरह से खिलाएं

पेट भरा हुआ होने से बच्चे को अच्छी नींद आएगी। अगर आप बच्चे को स्तनपान करवाती हैं तो उस पर भी ध्यान रखें कि उसने अच्छी तरह से दूध पी लिया हो। दिन में बच्चे को रोशनी में खाना खिलाएं लेकिन रात होने पर किसी शांत जगह पर और अंधेरे में ही खिलाएं। इससे बच्चे को अच्छी नींद आ जाती है।

दिन में कम सुलाएं

अगर बच्चे को पूरी रात बिना जगाए सुलाना है तो दिन में उसे कम सुलाएं। दिन में दूध या खाना खिलाने के तुरंत बाद सुला दें और फिर अपना सारा काम निपटा लें। पर उतना ही सुलाएं जितनी उसको जरुरत हो वरना ज्यादा सोने से उसे रात में नींद नहीं आएगी।

अपने बच्चे के पास रहें

सोते समय जब आप अपने बच्चे के पास लेटती हैं, तब बच्चा खुद को सुरक्षित महसूस करता है। कुछ बच्चों को यह महसूस हो जाता है कि मां उसके पास मौजूद नहीं है, इसलिये वह झट से उठ जाता है और रोने लगता है। इसलिये बच्चे के सोने के 10-15 मिनट बाद ही बिस्तर से उठें।

एक ही रूटीन का पालन करें

अगर बच्चे को एक समय पर ही सुलाना चाहती हैं तो रुटीन का पालन करें। कभी जल्दी और कभी देर से न सुलाएं, इससे आप ही को परेशानी होगी। बच्चे को रोज एक ही समय पर खाना खिलाएं और फिर सुलाएं।

आरामदायक बिस्तर

अगर कमरे में अंधेरा हो और मुलायम बिस्तर हो तो बच्चे को अच्छी नींद आती है। बच्चे के लिये एक अलग से कंबल या चादर रखें, इससे बच्चा आराम से खुद के बिस्तर और कंबल में बिना परेशानी के सो सकता है।

फायदेमंद है ममा का क्रिएटिव होना

नई-नई मम्मी बनी महिलाओं के अलावा ये खबर ममी टू बी ज के लिए भी बेहद अच्छी है। एक शोध ने बताया है कि पार्ट टाइम काम करने वाली या किसी भी अन्य क्रिएटिव काम में बिजी रहने वाली मम्मियां कई तरह की परेशानियों से दूर रह सकती हैं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। असल में पिछले दिनों हुए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया कि वे महिलाएं, जिन्होंने कुछ ही महीने या हफ्ते पहले बच्चे को जन्म दिया हो, अगर पार्ट टाइम किसी संस्थान में काम करती हैं या फिर घर में बच्चे की देखभाल से बचे समय में पेंटिंग, संगीत, लेखन या अन्य किसी क्रिएटिव काम से जुड़ी रहती हैं तो वे तनाव, डिप्रेशन आदि से काफी हद तक दूर रहती हैं।

यही नहीं अन्य महिलाओं की तुलना में ऐसी महिलाएं ज्यादा स्वस्थ भी रहती हैं और उनके बच्चे भी ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। असल में किसी भी काम में व्यस्त रहने से आपका दिमाग उन नकारात्मक चीजों में उलझने से बच जाता है जो आपको खाली बैठे में घेर सकती हैं। चाहे फिर वे नकारात्मक भावनाएं या उलझनें आपके परिवार, आस-पड़ोस या अन्य किसी भी मुद्दे से जुड़ी क्यों न हों।

साथ ही क्रिएटिव काम या मनपसंद काम को करने से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है वह बच्चे के साथ समय गुजारने में आपकी मदद करती है। वहीं भावनात्मक तौर पर भी आप मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए और मजबूत बनती हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप सेहत को नुकसान पहुंचाकर कोई काम शुरू करें या अपने आराम के समय से समझौता करें। असल बात सिर्फ मानसिक तौर पर आपके किसी क्रिएटिव चीज में डूबने से जुड़ी है। यानी दिमाग को अच्छी खुराक मिलेगी और आप बच्चे के साथ को और भी अच्छी तरह एंजॉय कर पाएंगी।

गर्मियों की बड़ी समस्या

एक्ने

अक्सर गर्म मौसम में तैलीय त्वचा वाले युवाओं को पीड़ाजनक एक्ने का अनचाहा सामना करना पड़ता है। बार-बार की सावधानियां भी इस तकलीफ को रोक नहीं पाती और पीडित झुंझला उठता है। कई बार सही जानकारी का अभाव भी एक्ने का जनक हो सकता है।

आप यही उदाहरण देख लीजिए

18 वर्षीय एक युवती के माथे पर अचानक छोटे-छोटे दाने उभर आए। बालों में कई समय से रूसी होने के कारण ये दाने हो गए थे। सौंदर्य समस्याएं कई बार सेहत से जुड़ी होती हैं। जैसा इस युवती के मामले में हुआ। दानों के उपचार के लिए उसकी त्वचा और बालों की रूसी का उपचार साथ-साथ किया, हेयर स्टाइल बदली ताकि बाल माथे पर न आएं। उसे रोज बालों को धोने की सलाह दी गई। साथ ही रूसी का उपचार भी शुरू किया गया।

हाजमा ठीक न होने से भी इस तरह की परेशानी हो सकती है। उसे रोज दिन में एक कटोरी दही खाने की सलाह दी गई। तीन महीनों के बाद उसके माथे के दाने गायब हो गए। माथे के दाने कई बार साधारण न होकर किसी संक्रमण के कारण हो सकते हैं।

हाजमा बिगड़ना भी एक कारण हो सकता है, इसके लिए भरपूर पानी पीना बहुत जरूरी है। माथे की त्वचा चेहरे की बाकी त्वचा से थोड़ी अलग होती है, वहां तेल ग्रंथियां ज्यादा होती हैं, इसलिए दाने भी सबसे पहले उभरते हैं।

इसी तरह अगर लिवर इंफेक्शन होने पर भी माथे पर दाने आ सकते हैं। हालांकि ऐसा हर बार हो ही, ऐसा जरूरी नहीं। साफ-सफाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने हाथों को दिन में कई बार साबुन से धोएं। चेहरे को सेलिसिलिक एसिड युक्त फेस वॉश से दिन में दो बार धोएं। बालों को छोटा रखें। अगर लंबे हों तो उन्हें पीछे की ओर बांधे। ध्यान रखें कि वे चेहरे पर न आने पाएं।

- अपने हाथों को चेहरे पर कम से कम लगाएं।
- हेड बैंड्स का प्रयोग न करें, क्योंकि वे पसीना सोखते हैं।
- धूम्रपान कम करें। एक्टिव स्मोकर्स में एक्ने ज्यादा होता है।
- हेयर स्प्रे बहुत सावधानी से करें क्योंकि इससे रोम छिद्र बंद हो सकते हैं। बालों को बांध कर रखें।

ध्यान दें कि बालों से शैंपू पूरी तरह साफ हो। बालों और माथे पर शैंपू के अंश रह जाने से कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।

गर्मी में लड़कियों के लिए

खास टिप्स

गर्मी ने आते ही सबके हाल बेहाल करना शुरू कर दिया है। इसका असर बच्चों व बूढ़ों पर पड़ा है, तो महिलाएं भी इससे अछूती नहीं रही हैं।

कामकाजी महिलाओं और लड़कियों को गर्मी के मौसम में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां हम महिलाओं को गर्मी से बचने के कुछ उपाय बता रहे हैं।

1. धूप में बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं। यह आपको सनबर्न, स्कीन टैन आदि से बचाएगा। आपका सनस्क्रीन SPF15 या उससे ज्यादा का होना चाहिए।
2. इसके साथ जब भी बाहर जाएं तो गॉगल, हैंड ग्लव्स और स्कॉर्फ भी पहनें।
3. अपने सिर को हमेशा ढंककर रखें।
4. हर 1 घंटे में पानी पीने का नियम बना लें। ऐसा करने से आपके शरीर में हाइड्रेशन लेवल बना रहेगा।
5. रसीले फलों का सेवन करें, जैसे अंगूर, तरबूज, आम, ककड़ी ये आपके शरीर को पोषण देने के साथ-साथ तरोताजा भी रखेंगे।
6. अपने चेहरे पर हफ्ते में एक बार हर्बल मॉइस्चराइजर लगाएं जिसमें चंदन, हल्दी, ब्राह्मी, आमला और एलोवीरा हो।
7. साथ ही 1 महीने में 2 बार फ्रुट मॉस्क भी लगाएं।
8. गर्मी के मौसम में बाहर रोड पर लगे नलों में से पानी पीना अवॉइड करें। अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें।
9. गर्मी के मौसम में 2 बार स्नान करें।
10. जरूरत से ज्यादा भी काम न करें। जितनी क्षमता हो, उतना ही काम करें।
11. चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन न करें तथा इन्हें खाली पेट तो बिलकुल न लें। खाली पेट लेने से पेट की बीमारियां होने की आशंका होती है।
12. और सबसे जरूरी कि अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। समय से सोएं और समय से उठें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक - नीलम सिंह गिल द्वारा देहात संदेश, गुरूद्वारा सुंदर सिंह रोड, जम्मू से प्रकाशित एवं नार्थलाईनस पबलिशर्स, 18-B, Phase- II, Industrial Estate, Gangyal, Jammu से मुद्रित। संपादक- नीलम सिंह गिल। फोन नंबरः- (95)191- 2574109 2548103 RNI Regd. No.: JKBIL/2004/13144 *Email: dehatsandesh@gmail.com, dehatsandesh@yahoo.com, dehatsandesh@rediffmail.com*

जीएमसी कठुआ में कर्मचारियों की हड़ताल शुरू, मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी

कठुआ, 01 अप्रैल (हि.स.)। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में जम्मू-कश्मीर मेडिकल इंप्लाइज फेडरेशन के बैनर तले ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा घोषित तीन दिवसीय हड़ताल बुधवार पहले दिन शुरू हो गई। इस हड़ताल को एनएचएम एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है।

हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार से अपनी जायज मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ढाई दिन की सैलरी लागू करना, फ्इक्वल वर्क इक्वल पेफ् नीति को प्रभावी बनाना तथा सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को जल्द अधिसूचित करना शामिल है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से अपील की कि उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान निकाला जाए, ताकि कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष को खत्म किया जा सके और वे बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं दे सकें। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करते हुए बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा

आईजीआर ने कोर्ट परिसर का किया दौरा, भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने पर जोर

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की दिशा में अहम प्रगति दर्ज की गई है। अतिरिक्त महानिरीक्षक पंजीकरण (आईजीआर) आबिद हुसैन ने अतिरिक्त उपायुक्त बडगाम मेहराज-उद-दीन और सब-रजिस्ट्रार के साथ कोर्ट कॉम्प्लेक्स बडगाम का दौरा कर पुराने पंजीकरण रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को बताया गया कि अब तक लगभग 70 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों ने शेष कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया, ताकि सभी रिकॉर्ड को एकीकृत कर सुचारू सेवा सुनिश्चित की जा सके। यह पहल डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को केंद्रीकृत करना, संपत्ति विवादों को कम करना और लोगों को तेज, पारदर्शी व सुरक्षित सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत पिछले दो दशकों के रिकॉर्ड को राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) पर अपलोड किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पहले संपत्ति पंजीकरण का कार्य न्यायपालिका के पास था लेकिन अब यह जिम्मेदारी पंजीकरण विभाग को सौंप दी गई है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड अभी भी अदालतों में मौजूद हैं जिन्हें डिजिटल करना जरूरी है।

सांसद गुलाम अली खटाना ने उठाया जम्मू-कश्मीर में शिक्षा योजनाओं का मुद्दा

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। राज्यसभा में वरिष्ठ भाजपा नेता और नामित सांसद गुलाम अली खटाना ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक अतारांकित प्रश्न उठाया। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को लगातार सहयोग दे रही है।

मंत्री ने बताया कि पीएम-उषा के तहत जम्मू-कश्मीर में 74 इकाइयों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 706.41 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र का हिस्सा 636.56 करोड़ रुपये है, जिसमें से 20 मार्च 2026 तक 406.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

वहीं समग्र शिक्षा के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में हजारों करोड़ रुपये प्रस्तावित, जारी और व्यय किए गए हैं, जिससे स्कूल शिक्षा को मजबूती मिली है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूल योजना के तहत भी 2023-24 से 2025-26 के बीच सैकड़ों करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और चरणबद्ध तरीके से धनराशि जारी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से स्कूलों में कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल, बिजली, पुस्तकालय और आईसीटी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा को दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी भारतनेट के तहत मजबूत की जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षक रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से योजनाओं की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। केंद्र सरकार ने दोहराया कि वह जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जम्मू के प्रणव संभयाल बने इंटरनेशनल शूटिंग जज

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। भारतीय शूटिंग खेलों के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि में जम्मू के प्रणव संब्याल ने इंटरनेशनल शूटिंग जज के रूप में क्वालिफाई कर भारत के साथ साथ जम्मू का भी नाम रौशन किया है। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) 'बी' जजेस कोर्स 28 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक क्राउन प्लाजा नई दिल्ली ओखला में आयोजित किया गया। इस कोर्स का संचालन ग्रेट ब्रिटेन के पॉल गाम और जापान के वातारू फुजी जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारत, जापान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित चार देशों के कुल 36 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिससे यह प्रतियोगिता काफी प्रतिस्पर्धात्मक और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बन गई। प्रणव संभयाल जो पहले ही राष्ट्रीय स्तर के शूटिंग जज रह चुके हैं ने इस कोर्स में अपनी तकनीकी समझ, नियमों की गहरी जानकारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। उनकी यह उपलब्धि शूटिंग खेलों में उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाती है।

उन्होंने विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों को सहयोग देने, प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने और खेल में निष्पक्षता व पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया है। उनकी इस सफलता से भारत की अंतरराष्ट्रीय शूटिंग जगत में स्थिति और मजबूत होगी तथा यह उपलब्धि युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी।

नशे के मामले में फंसा पुलिसकर्मी बर्खास्त, एसएसपी उधमपुर की सख्त कार्रवाई

उधमपुर, 01 अप्रैल (हि.स.)। नशीले पदार्थों के मामले में संलिप्त पाए जाने पर उधमपुर पुलिस के एक कांस्टेबल को सेवा से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, कांस्टेबल अर्जुन शर्मा (नंबर 886/यू) के खिलाफ थाना रैंबन में एफआईआर नंबर 170/2025 के तहत एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज था। विभागीय जांच और पुलिस जांच में यह सामने आया कि टिकरी पुलिस पोस्ट की टीम ने नाका चेकिंग के दौरान आरोपी के कब्जे से हेरोइन बरामद की थी, जिसकी पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट में भी हुई। जांच में आरोपी का कृत्य गंभीर और पुलिस सेवा के विरुद्ध पाया गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए एसएसपी उधमपुर ने जेके पुलिस नियम 359 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। उधमपुर पुलिस ने दोहराया है कि नशे के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है

श्रीनगर-बारामूला हाईवे के लिए वन भूमि डायवर्जन पर सरकार को 3.83 करोड़ की वसूली

जम्मू 01 अप्रैल (हि.स.)। सरकार ने विधानसभा में जानकारी दी कि श्रीनगर-बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए वन भूमि के डायवर्जन के एवज में मुआवजा वनीकरण और नेट प्रेजेंट वैल्यू के तहत कुल 3.83 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

जल शक्ति, वन, पर्यावरण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने विधायक डॉ. सज्जाद शफी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि यूजर एजेंसी ने 96.43 लाख रुपये मुआवजा वनीकरण और 2.87 करोड़ रुपये एनपीवी के रूप में जमा किए हैं। मंत्री ने कहा कि डायवर्जन के बदले वनीकरण और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन के कार्य किए गए हैं। 27 हेक्टेयर क्षेत्र में 27 हजार पौधे लगाने की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि यह कार्य वर्ष 2024-25 में ही पूरा किया जा चुका है। पर्यावरण सुरक्षा उपायों के तहत बीआरओ द्वारा प्रभावित क्षेत्र में ढलान स्थिरीकरण कार्य किए जा रहे हैं। डीपीआर के अनुसार 22,315 मीटर दीवारों का निर्माण प्रस्तावित था, जिसमें से 15,900 मीटर कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने बताया कि बारामूला जिले में इस परियोजना के लिए कुल 20.93 हेक्टेयर वन भूमि डायवर्ट की गई है और विकास कार्यों को पर्यावरणीय संतुलन के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

परशुराम जयंती महोत्सव की तैयारियां तेज, शिव नगर में हुई बैठक

कठुआ, 01 अप्रैल (हि.स.)। आगामी परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर श्री ब्राह्मण सभा कठुआ ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शिव नगर स्थित मंदिर में सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र मेहता की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव को भव्य और सफल बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सदस्यों और स्थानीय लोगों ने परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए अपने-अपने सुझाव रखे। इस दौरान महिला विंग की उपाध्यक्ष शोभा रानी, मंदिर के सदस्य हरबंस लाल सहित शिव नगर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अध्यक्ष सुरेंद्र मेहता ने बताया कि महोत्सव को लेकर कठुआ शहर और आसपास के गांवों में लगातार बैठकें की जा रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे बढ़-चढ़कर इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लें और इसके प्रचार-प्रसार में सहयोग करें। उन्होंने जानकारी दी कि परंपरा के अनुसार परशुराम जयंती से सात दिन पहले भागवत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद जयंती के दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को भव्य रूप देने के लिए सभी से सहयोग और सहभागिता की अपील की गई। बैठक में श्री ब्राह्मण सभा के सदस्य अनिल भारद्वाज, बालकृष्ण शर्मा, सुनील शर्मा सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।

श्रेया सिंघल ने संभाला सूचना निदेशक जम्मू-कश्मीर का पदभार

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। आईएएस अधिकारी श्रेया सिंघल ने बुधवार को सूचना निदेशक, जम्मू-कश्मीर का पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआर) के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ परिचयात्मक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने पारदर्शी, समयबद्ध और जन-केंद्रित सूचना प्रसार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना विभाग सरकार और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है और विकासात्मक योजनाओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना आवश्यक है।

नव नियुक्त निदेशक ने संचार रणनीतियों को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ाने, मीडिया समन्वय को सुदृढ़ करने और हितधारकों के साथ सकारात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना (मुख्यालय) डॉ. जहूर अहमद रैना, संयुक्त निदेशक सूचना जम्मू दीपक दुबे, उप निदेशक सूचना (पीआर एंड एवी) जाविद अहमद राथर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एमएसई ने इक्विटी सेगमेंट के लिए मार्केट मेकर्स की नियुक्ति पूरी की

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएसई) ने अपने इक्विटी सेगमेंट के लिए मार्केट मेकर्स की नियुक्ति सफलतापूर्वक पूरी करने की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण कदम से बाजार में गहराई बढ़ने, कीमतों की सही खोज (प्राइस डिस्कवरी) को मजबूती मिलने और निवेशकों के लिए ट्रेडिंग अनुभव बेहतर होने की उम्मीद है। एमएसई ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से एक्सचेंज में तरलता (लिक्विडिटी) बढ़ाने के लिए विशेष उपाय लागू किए जाएंगे।

जम्मू में सॉफ्टबॉल जेएन्डके चैंपियनशिप 2025-26 का भव्य समापन

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सॉफ्टबॉल जेके चैंपियनशिप 2025-26 का बुधवार को समापन हो गया। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पूरे जम्मू-कश्मीर से करीब 400 खिलाड़ियों ने सब-जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में हिस्सा लिया। समापन समारोह में मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेएन्डके स्पोर्ट्स काउंसिल के सचिव सहित जम्मू और कश्मीर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल ढांचे को मजबूत करने, बेहतर प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रतियोगिता के परिणामों में सब-जूनियर और जूनियर गर्ल्स वर्ग में जम्मू ने स्वर्ण पदक जीतकर दबदबा बनाया। सीनियर गर्ल्स में पुलवामा ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि श्रीनगर और उधमपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

बॉयज वर्ग में सब-जूनियर और जूनियर दोनों श्रेणियों में श्रीनगर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि सीनियर पुरुष वर्ग में जम्मू ने स्वर्ण पदक जीता। यह चैंपियनशिप नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित की गई जिसमें ड्रग्स को ना और खेल को हां का संदेश दिया गया। अंत में विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया, रैम्प सहित कई योजनाओं की दी गई जानकारी

जम्मू, 01 अप्रैल (हि.स.)। जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) डोडा द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में एमएसएमई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उपायुक्त कृष्णलाल और महाप्रबंधक डीआईसी मोहम्मद अशफ़ाक के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए। यह शिविर 30 मार्च को सरकारी आईटीआई डोडा में कस्तीगढ़ और घाट ब्लॉकों के लिए तथा 31 मार्च को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज डोडा में भगवाह ब्लॉक के लिए आयोजित किए गए जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं, उद्यमियों, व्यापारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों में एमएसएमई प्रदर्शन बढ़ाने और तेज करने योजना (आरएएमपी) के तहत एमएसएमई को वित्तीय सहायता, बाजार से जुड़ाव, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही एमएसएमई हेल्थ क्लीनिक के माध्यम से संकटग्रस्त इकाइयों के पुनर्वास और वित्तीय पुनर्गठन के उपाय भी बताए गए। शिविरों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाओं, केंद्रीय एमएसएमई योजनाओं, जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति और स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया।

युवाओं को प्रोजेक्ट तैयार करने, कौशल आधारित उद्यम चुनने, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने और संस्थागत ऋण प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। इसके अलावा व्यापार सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) के तहत सुधारों, स्टार्टअप सेल और बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए रिलेशनशिप ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ संवाद सत्र भी आयोजित हुआ जिसमें उनके सवालों का समाधान किया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जिले में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग हर संभव सहयोग जारी रखेगा।

Union Territory of Jammu and Kashmir
Office of the Divisional Forest Officer
Kathua Forest Division Kathua
Email Id: dfokathua.for-jk@nic.in
Office Address: Forest Complex College Road Kathua Ph / Fax No. 01922-453735

FINAL PUBLIC NOTICE

Subject: Final Public Notice inviting objections/claims regarding seized vehicles involved in illegal smuggling of Khairwood.

Whereas, this office had earlier issued a 1st Public Notice vide letter No. KFD/2025-26/4571-74 dated 07/03/2026 and subsequently a 2nd Public Notice vide No. KFD/2025-26/4705-08 dated 20/03/2026, inviting claims/objections from the general public regarding the ownership or any interest in the seized vehicles involved in cases of illegal smuggling of Khairwood.

Wherein, a period of 07 (Seven) days from the date of publication of each notice in print media was provided to submit claims, objections, or ownership interests along with supporting documentary evidence before the undersigned.However, it is hereby brought to the notice of the general public that even after the lapse of more than 20 days from the issuance of the aforementioned notices, no claim or objection has been received before the forum of the Authorized Officer (Divisional Forest Officer), Forest Division, Kathua.

Therefore, through this **Final Public Notice**, it is once again informed that if any person(s) has any claim, objection, or interest regarding the ownership of the seized vehicles pertaining to the concerned cases, they may submit the same in writing along with supporting documentary evidence before the undersigned within 07 (Seven) days from the date of publication of this notice.Failing which, it shall be presumed that no person has any claim or objection with respect to the said seized vehicles, and further legal proceedings shall be initiated under Section 52(3) of the Indian Forest Act, 1927, without any further notice.

The details of the seized vehicle/stuff are tabulated below:

S. No.	FOR No.& Year	Date	Name of person from possession vehicle/timber seized	Place of seizure	Vehicle/Species	Quantity in Nos./Qtls/ CFT	Seized stuff/vehicle lying at
1)	126/2025-26	05.02.2026	Unknown	Hiranagar	JK02AA-9121/ khairwood	10 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar
2)	127/2025-26	15.02.2026	Unknown	Village Kongni, Mangloor	JK13-8784/khair-wood logs	70 nos. of khairwood billets approx. 12 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar
3)	125/2025-26	09.02.2026	Unknown	Police Station Rajbagh	Alto Car Regd No. PB35F-9555/khairwood logs	12 nos. of khairwood billets approx. 03 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar
4)	48/2025-26	03.07.2025	Unknown	Village Kheri Tehsil Dinga Amb	JK08N-9113/ khair-wood	13 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar
5)	62/2025-26	09.10.2025	Unknown	Village Banayari, Tehsil Marheen	JK08E-3658/ khair-wood	25 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar
6)	89/2025-26	23.11.2025	Unknown	Logate Tehsil & District Kathua	PB35H-2644/ khair-wood billets	05 billets having volume 0.4933cum	Forest Complex, kathua
7)	92/2025-26	04.12.2025	Unknown	Ghatti	PB08CQ-8990/ khair-wood billets	12 billets having volume 0.47456 cum	Forest Complex, Kathua
8)	101/2025-26	25.12.2025	Unknown	Korepunnu Tehsil Marheen	JK14D-7118/ khairwood	20 nos. of billets having weight approx. 05	Haria Chack Nursery, Jasrota Forest Range
9)	107/2025-26	14.01.2026	Unknown	Barn Tehsil Marheen District Kathua	JK08D-9391/ khairwood	40 nos. of billets having weight approx. 15 Qtls	Range Forest Office, Complex Hiranagar

This is issued for wide publicity in the interest of justice.

Sd/-
Ankit Sinha, IFS
(Authorized Officer)
Divisional Forest Officer
Kathua Forest Division
Kathua

DIP/J-32/26
Dtd:1-4-2026

संपादकीय

निजी स्कूलों पर निगरानी रखें

यह सराहनीय है कि शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री Sakeena Itoo ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फैसले लेकर अभिभावकों पर अनुचित आर्थिक बोझ डालने के मुद्दे का संज्ञान लिया है। बताया जाता है कि शिक्षा मंत्री ने जेकेबोस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश सिविल सचिवालय में आयोजित एक व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान दिए, जिसमें जेकेबोस के प्रदर्शन, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और चल रहे शैक्षणिक सुधारों का आकलन किया गया। ऐसे कदम इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि क्षेत्र में कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने जैसी शोषणकारी प्रवृत्तियाँ अपनाते हैं और अभिभावकों को किताबें, यूनिफॉर्म, बैग, यहाँ तक कि कुछ मामलों में पानी की बोतलें और पेंसिल बॉक्स भी तय दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि अतिरिक्त लाभ कमाया जा सके।

हालांकि अपने दृष्टिकोण और मिशन दस्तावेज़ों में ये स्कूल राष्ट्र के भविष्य को संवारने और समग्र शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत दिखाई देती है। निजी स्कूलों द्वारा इस तरह की मनमानी कोई नई बात नहीं है; यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और अभिभावक इसके शिकार होते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

इसलिए आवश्यक है कि सरकार उच्च स्तर पर ठोस नियम बनाए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, ताकि कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों का शोषण न कर सके। शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश समयानुकूल और आवश्यक हैं, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में नियमों का सख्ती से पालन कराना बेहद जरूरी है।

सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन गंभीरता से लिया जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्कूलों की मान्यता रद्द करना भी शामिल है। ऐसे कदम निजी स्कूलों को अनैतिक गतिविधियों से रोकने और अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने से बचाने के लिए जरूरी हैं।

सरकार को समय-समय पर स्कूलों के खातों का ऑडिट भी करना चाहिए और इन संस्थानों को अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने चाहिए, जिससे विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, अभिभावकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि वे किसी भी अनुचित मांग के खिलाफ आवाज उठा सकें।

अंतत:, शिक्षा मंत्री को इस मामले में निरंतर निगरानी और फॉलो-अप भी करना चाहिए, ताकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को न्यायसंगत और पारदर्शी व्यवस्था मिल सके।

भारत के लिए मुद्रा योजना बनी सूक्ष्म उद्यमों की ताकत

– डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ों में यदि किसी क्षेत्र की सबसे अधिक भूमिका है, तो वह है सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विशाल नेटवर्क की। यही कारण है कि वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाने बीते एक दशक में देश के करोड़ों लोगों को वित्तीय सहारा देने के साथ आर्थिक संरचना को भीतर से मजबूत करने का कार्य किया है। हालिया फैक्ट-शीट के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 52.37 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से 33.65 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

वस्तुत- भारत में लंबे समय तक छोटे उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी समस्या रही है कि बिना गारंटी के सुलभ ऋण की उपलब्धता कैसे संभव हो सकती है। पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था में जटिल प्रक्रियाओं और गारंटी की शर्तों के कारण छोटे कारोबारी अक्सर वित्तीय सहायता से वंचित रह जाते थे। ऐसे में मुद्रा योजना ने इस बाधा को तोड़ते हुए बैंक, एनबीएफसी और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराकर उद्यमिता को नई दिशा दी। यही कारण है कि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भारत में वित्तीय समावेशन की दिशा में इस प्रकार के प्रयासों को महत्वपूर्ण माना है। विश्व बैंक की रिपोर्टों में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय पहुंच का विस्तार आर्थिक असमानता को कम करने और विकास को समावेशी बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है।

मुद्रा योजना की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। कुल ऋणों में लगभग 70 प्रतिशत महिला उद्यमियों को दिए गए हैं, जोकि यह दर्शाता है कि उक्त योजना सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बनी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाएं अब स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं।

नीति आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से समग्र विकास दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सामाजिक संतुलन भी मजबूत होता है।

इसी तरह, सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत प्रभावी साबित हुई है। लगभग 50 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को दिए गए हैं। वस्तुत- यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि योजना ने आर्थिक अवसरों को समाज के उन वर्गों तक पहुंचाया है।

इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टों में भी इस बात पर बल दिया गया है कि समावेशी विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है और मुद्रा योजना इस दिशा में एक मजबूत कदम है। दरअसल योजना की संरचना को देखें तो इसे तीन प्रमुख श्रेणियों शिशु, किशोर और तरुण में विभाजित किया गया है, जिसे कि उद्यमों के विभिन्न विकास चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। शिशु श्रेणी में 50 हजार रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं और कुल ऋणों का लगभग 78 प्रतिशत इसी श्रेणी में है।

वस्तुत- यह दर्शाता है कि देश में बड़ी संख्या में लोग छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। वहीं किशोर श्रेणी, जिसमें 50 हजार से पांच लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं। कुल संख्या का लगभग 20 प्रतिशत है, लेकिन राशि के लिहाज से इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। इससे यह संकेत मिलता है कि छोटे व्यवसाय अब विस्तार की ओर बढ़ रहे हैं। तरुण श्रेणी में पांच से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं, जिसकी संख्या भले ही सिर्फ दो प्रतिशत है, किंतु कुल राशि में इसकी हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है, जोकि यह दर्शाती है कि विकसित हो रहे उद्यमों की पूंजी आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही हैं।

सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'तरुण प्लस' श्रेणी की शुरुआत की है जिसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उन उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने पहले मुद्रा ऋण लेकर अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और अब उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही 'क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स' के माध्यम से ऋण पर गारंटी कवरेज प्रदान किया जा रहा है, जिससे वित्तीय संस्थानों का जोखिम कम होता है और उद्यमियों को आसानी से ऋण मिल पाता है।

यहां अच्छी बात यह है कि मुद्रा योजना का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर तक सीमित न होकर इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिला है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टों के अनुसार, छोटे और सूक्ष्म उद्यम विकासशील देशों में रोजगार सृजन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। भारत में भी इस योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इससे देश की बेरोजगारी में कमी आई है, साथ में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूती मिली है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना असंगठित क्षेत्र को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनी है। जब कोई उद्यमी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ता है, तो उसका वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होता है, जिससे उसे भविष्य में और अधिक वित्तीय अवसर प्राप्त होते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने भी अपनी रिपोर्टों में भारत को डिजिटल और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है और मुद्रा योजना इस परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

इस तरह समग्र रूप से देखें और इसके बारे में कहें तो आज यही कहना होगा कि कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भारत की अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन की नींव रखी है। यह योजना उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने का एक सशक्त माध्यम है। आने वाले समय में यदि इसे कौशल विकास, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैश्विक बाजारों से जोड़ दिया जाएगा तो यह भारत को विश्व की अग्रणी उद्यमशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। देखते हैं भारत सरकार अब इस बारे में क्या निर्णय लेती है!

सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 'तरुण प्लस' श्रेणी की शुरुआत की है जिसके तहत 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह उन उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर है, जिन्होंने पहले मुद्रा ऋण लेकर अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित किया है और अब उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री हनुमान : रामभक्ति के विग्रहवान स्वरूप

–डॉ. उमेश चन्द्र शर्मा

हनुमान जी महाराज, परात्पर ब्रह्म, सच्चिदानन्द स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम के निष्ठावान सेवक, निष्काम भक्त और उनके अन्तरङ्ग पार्षद हैं। रामभक्ति के विग्रहवान स्वरूप श्री हनुमानजी भक्ति की उच्चतम पराकाष्ठा पर आसीन है और उनके जीवन में प्रेमा भक्ति, तात्विक ज्ञान और निष्काम कर्म योग का समुच्चय विद्यमान है।

श्री हनुमानजी राम मिलन के प्रमुख सेतु हैं और अपने आराधकों को जीवन के चरम लक्ष्य रामभक्ति की और अग्रसर करते हैं, वे रामभक्तों के परम आश्रय और संकटापन्न स्थिति में उनके संकटों का निवारण करते हुए उनके जीवन में शुभ मङ्गल का संचार करने वाले प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं।

भगवान् श्रीराम की वनगमन लीला में एक प्रमुख पात्र के रूप में उनकी भूमिका अपने स्वामी श्रीराम के निष्ठावान सेवक के रूप में ही नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर पुत्र के समान आज्ञाकारी, बंधु के समान हितकारी, द्विविधा की स्थिति में गुरु के समान पथ प्रदर्शक तथा विषम परिस्थितियों में मित्र के समान सहयोगी के रूप में भी उल्लेख किए जाने योग्य है। वस्तुत- हनुमानजी जैसा निष्ठावान, समर्पित एवं निष्काम भक्त न तो सृष्टि में पहले कभी हुआ और न आगे कभी हो सकता है। उनके बगैर श्रीरामचरित का पूरी तरह बखान नहीं किया जा सकता।

विराट वैभव से परिपूर्ण श्री हनुमानजी विनयशील हैं और रामकाज में अत्यंत लघु रुप धारण कर लेते हैं। हनुमानजी भगवान् श्रीराम की आज्ञा पाकर जब सीता माता की खोज हेतु निकले तो वे अत्यंत लघु रूप में आकाश मार्ग से गमन करते हुए लंका पहुंचे।

श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका की भूमि पर कदम रखने के पहले जहां उन्होंने अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण करते हुए लंका की सीमा में प्रवेश किया, वहीं जब लंका नगरी में माता सीता की खोज शुरू की, तब भी लघु रूप धारण कर सर्वप्रथम अपने स्वामी श्रीराम का स्मरण करते हुए सीताजी का अनुसंधान करने लगे।

हनुमानजी शुद्ध भक्त हैं इसलिए अहंकार रहित हैं और उनके द्वारा रामकाज निष्पादन हमें प्रेरित करता है कि किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटा हो जाना ही ठीक है। अहंकार महान् उद्देश्यों की पूर्ति में सदैव बाधक होता है, परिणामस्वरूप अहंकार से कोई महान् कार्य अपने मुकाम पर पहुंचने में पूरी तरह सफल नहीं होता इसलिए हनुमानजी अपने स्वामी श्रीराम की आज्ञा पाकर जब सीता माता की खोज हेतु निकले तो अपने मुख में राम नाम की विराट सत्ता को स्थापित कर लिया किंतु अपने स्वरूप को अत्यंत लघु आकार देते हुए लंकापुरी में सीता माता की खोज करने लगे।

धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान् शिव द्वारा अपने स्वामी श्रीराम की सेवा की तीव्र अभिप्सा के निमित्त उन्होंने ग्यारहवें रुद्र के रूप में वायुदेव केसरी और देवी अञ्जना के पुत्र हनुमान के रूप में जन्म लिया और भगवान् श्रीराम की सेवा की अपनी अभिलाषा पूरी की। पुराणों के अनुसार चूंकि भगवान् विष्णु ने रामावतार में पुरुष रुप धारण किया था और भगवान् शिव उनकी सेवा के अभिलाषी थे, ऐसे में यदि मनुष्य रूप में जन्म लेकर सेवा करते तो यह दास भाव के अनुकूल नहीं होता इसलिए उन्होंने मनुष्य से निम्नतर वानर योनि में जन्म लेकर दास भाव से अपने स्वामी भगवान् श्रीराम की सेवा की।

श्रीरामचरितमानस के अनुसार हनुमानजी ने गतिमान सूर्यदेव से तादात्म्य स्थापित करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण की, अपने दिव्य गुणों से वे सूर्यदेव के भी स्नेह भाजन हुए और उनसे प्रखर बुद्धि, दिव्य ज्ञान सहित तेज, ओज, बुद्धि और बल पा गए।

वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि एवं हनुमान बाहुक में गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जब श्री हनुमान विद्या अध्ययन हेतु भगवान् सूर्य के पास गए तो सूर्यदेव ने असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सदैव गतिमान हूं और तुम्हारे लिए मेरे सामने बैठना संभव नहीं इसलिए मैं तुम्हे कैसे शिक्षा दूंगा? तभी हनुमानजी ने सूर्याभिमुख होकर आकाश मार्ग में गमन करना शुरू कर दिया और उनके समक्ष उनसे संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। उधर स्वर्ग स्थित देवताओं ने जब यह अद्भुत एवं विस्मयकारी दृश्य देखा तो सब के सब हतप्रभ रह गए और हनुमानजी के धैर्य, शौर्य, साहस और वीरता की प्रशंसा करने लगे।

हमारे वेद, उपनिषद् एवं पौराणिक ग्रंथों में भगवान् श्रीराम के पावन नाम की बड़ी महिमा का बखान किया गया है और हनुमानजी महाराज तो भगवान् श्रीराम के अतिप्रिय दास हैं, रुद्रावतार हैं और रुद्र अर्थात शिव सतत रामनाम में ही रत रहते हैं, ऐसे में रुद्रावतार हनुमानजी हर क्षणांश अपने प्रभु के नाम का ही स्मरण किया करते हैं।

श्री बुधकौशिक मुनि रामरक्षा स्तोत्र में भगवान् शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद का उल्लेख करते हुए, रामनाम की महिमा का वर्णन करते हैं-राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने।।

अर्थात है देवी ! राम राम राम इस प्रकार तीन बार राम नाम का उच्चारण सहस्त्र नाम के तुल्य है इसलिए मैं सदैव राम नाम में ही रमण करता हूं।

श्री हनुमानजी पर ब्रह्म एवं शक्ति की महती कृपा थी और वे इसी शक्ति से अनुप्राणित हुए। वाल्मीकि कृत रामायण सहित अन्य पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान् श्रीराम और भगवती सीता द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद से श्री हनुमानजी अजर अमर हैं और कल्प पर्यन्त पृथ्वी लोक में उनका निवास बना रहेगा।

महर्षि वाल्मीकि के अनुसार भगवान् श्रीराम के आज्ञानुसार सीता माता की खोज कर लौटे हनुमानजी को प्रभु ने अपना सर्वस्व कहा जाने वाला दिव्य आलिंगन प्रदान कर उन्हें कृत-कृत कर दिया और जब प्रभु अपनी लीलाओं का संवरण कर अपने नित्य धाम जाने लगे तब उन्होंने हनुमानजी को कहा कि हनुमान! तुम मेरी कथा में ही मेरी भावना कर कल्प पर्यन्त इस पृथ्वी लोक पर निवास करते हुए स्वयं मेरी कथा सुनना और रसिकों को भी सुनाया करना।

ऋषि वाल्मीकि के अनुसार भगवान् श्रीराम ने हनुमानजी को कहा कि जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं स्थिर रहेंगी और जब तक मेरी कथा संसार में रहेगी, तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे और तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी। भगवान् श्रीराम की कृपा के साथ ही सीताजी ने भी हनुमानजी पर कृपा करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि हे तात! तुम बल और शील के निधान, अजर अमर और गुणों की निधि होओ और श्रीरघुनाथजी तुम पर बहुत कृपा करें।

बजट से वोटबैंक बढ़ाने की कवायत

–मनोज कुमार मिश्र

27 साल लंबे अंतराल के बाद दिल्ली की सत्ता पाने वाली भाजपा ने अपने दूसरे ही बजट में वह सारी घोषणाएं की है, जिससे उसके स्थाई वोट बैंक में बढ़ोतरी हो सके। लगातार तीन बार दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों और साल 2022 से पहले के तीन नगर निगम चुनाव जीतने वाली भाजपा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार छह बार पराजित रही लेकिन पिछले साल केवल ढाई फीसदी के अंतराल से चुनाव जीतकर सत्ता में आई।

इसी 24 मार्च को 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने इसे हरित बजट का नाम दिया। इस बजट में जिस तरह की दनादन घोषणाएं की गई हैं, उससे वास्तव में यह चुनावी बजट जैसा लगता है। अगले साल के आखिर में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का एक और बजट ही आ पाएगा। नगर निगम चुनाव 05 दिसंबर, 2022 को हुए थे। साल 2022 से पहले तीन नगर निगम चुनाव जीतने के बावजूद भाजपा का वोटबैंक नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें अपवाद लोकसभा चुनाव ही है। जिसमें भाजपा को दिल्ली में औसत 50 फीसदी से ज्यादा वोट मिलते रहे हैं।

इस बजट का फोकस महिला वर्ग है। महिलाओं का समर्थन मिलने से ही बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में लगातार राजग और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती रही है। इसी के बूते महाराष्ट्र में फिर से राजग की सरकार बनी। लाडली योजना के बजाए लखपति बिटिया योजना, बिहार की तर्ज पर 9 वीं की 1.30 लाख बच्चियों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी। बजट पेश होने के साथ इस पर अमल करते हुए एक समारोह में 1100 बच्चियों को मुख्यमंत्री ने साइकिल बांटी। इस पर सरकार 90 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 10वीं के मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप देने पर दस करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। इस पर भी अमल शुरु हो गया है।

महिलाओं की तरह किन्नरों को भी बसों के फ्री पास, एक हजार महिलाओं और 100 किन्नरों को ई-आटो की परमिट, महिला सुरक्षा के तहत डार्क स्पाट खत्म करने और महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के मद में 5110 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह अलग विषय है कि सरकार बने साल बीत जाने के बावजूद महिलाओं को पैसे मिलना शुरु नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समिति बनाकर पात्र महिलाओं की पहचान की गई। अब तुरंत नियमित पैसे दिए जाएंगे।

इस बार बजट में 3700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।

27 साल बाद पिछले साल फरवरी दिल्ली में बनी भाजपा सरकार ने साल 2025-26 का रिकार्ड एक लाख करोड़ का बजट पेश किया। विधानसभा चुनाव में जिस तरह के वायदे किए गए थे, उसमें यह बजट भी नाकाफी रहा। दिल्ली में दस साल प्रचंड बहुमत से सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी (आआपा) पर भाजपा समेत सभी विरोधी दल मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का आरोप लगाती रही। अब भाजपा सरकार भी उन मुफ्त की रेवड़ियों को दूसरे साल भी जारी रखने का ऐलान किया। भाजपा को इसका फायदा समझ में आने लगा है। इतना ही नहीं, दनादन मुफ्त बिजली-पानी के अलावा बजट में कई और रेवड़ियों की घोषणा कर दी। इस साल भी होली-दीवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर 260 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह दिल्ली को और हरा-भरा बनाने वाला हरित बजट है। बजट मद का 21 फीसदी धन दिल्ली को हरा-भरा बनाने पर खर्च किया जाएगा। दिल्ली में ई-आटो, ई-टैक्सी और ई-बसें बड़ी तादाद में चलाई जाएंगी। दिल्ली के अलावा एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में ई-बसों का परिचालन शुरु हो गया है। मेट्रो रेल के चौथे और पांचवें चरण की न केवल मंजूरी दी गई है बल्कि उसके लिए 2224 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया गया है। इसी तरह नमो भारत के दो नए कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 568 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली नगर निगम को इस बार सर्वाधिक 11,666 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यार्थी राजनीति के बाद नगर निगम से ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। तीन निगमों को एक करके 272 सीटों को 250 सीट करके पांच दिसंबर, 2022 में निगम चुनाव करवाए गए। लगातार तीन बार से निगम की सत्ता में रही भाजपा उस चुनाव में पिछड़ गई और 134 सीटें लाकर आआपा पहली बार नगर निगम की सत्ता में आ गई। उसे हर बार 36 फीसदी के आसपास वोट मिलते रहे। भाजपा को 106 सीटें आई। नगर निगम में दलबदल विरोधी विधेयक लागू नहीं है। दो साल में दल बदलने वाले निगम पार्षदों के बूते भाजपा फिर से निगम में बहुमत में आ गई। सालों बाद केन्द्र के बाद दिल्ली की सत्ता में भाजपा के आने के बाद वह किसी भी तरह से अगले साल होने वाले चुनाव को जीतने का प्रयास करेगी।

वैसे अभी सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है। उसका सामना करने और उसका निबटारा करने के लिए सरकार को लगातार युद्धस्तर पर काम करना होगा। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के अलावा दिल्ली के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा। इस बजट में नया सचिवालय, कई सरकारी उपक्रमों के भवन और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास बनाने इत्यादि की घोषणा की गई है। दस केन्द्रीय विद्यालय और एक सैनिक स्कूल बनाने के वायदे किए गए हैं। पहले के विश्वविद्यालयों के कैंपस बनाने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं।

वायदे के मुताबिक मंत्रिमंडल की पहली बैठक में आम लोगों को मुफ्त उपचार के लिए आयुष्मान योजना न केवल दिल्ली में लागू किया गया।

अबतक इस योजना में सात साख से ज्यादा लोग पंजीकरण कराकर इसका लाभ उठा रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या और वार्ड आदि बढ़ाने की घोषणा तो की गई है लेकिन नए अस्पताल बनाने की घोषणा नहीं हुई है। दिल्ली में देश का सर्वाधिक न्यूनतम वेतन 22,411 रुपए प्रति महीना लागू किया गया।

कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए पांच सौ पालन केन्द्र खोले गए हैं। परिवहन क्षेत्र में चार हजार से अधिक ई-बसें चलाई गई है। नौ हजार से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। नई ईवी नीति, ई- बाइक, ई-टैक्सी को बढ़ावा देने के अलावा दिल्ली के आखिरी छोर तक सार्वजनिक वाहन को पहुंचाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। वैसे सरकार को हाई कोर्ट के हलफनामे के हिसाब से 11 हजार बसों को सड़क पर लाने की भी चुनौती है।

37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 28 को अपग्रेड किया गया है, नौ पर काम चल कहा है। 12 नए संयंत्र बनेंगे। दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने से लेकर दिल्ली के मूलभूत ढांचे को विकसित करने से लेकर दिल्ली को आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त शहर बनाने के प्रयास के लिए दिल्ली सरकार केन्द्र की सरकार के सहयोग से दिन-रात काम कर रही है।

1993 में दिल्ली में नए प्रशासनिक ढांचे में विधानसभा बनने पर हुए पहले चुनाव में भाजपा की सरकार बनी। पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद उस सरकार ने कई ठोस काम किए। पहली बार यमुना के जल में राज्य की तरह दिल्ली को हिस्सा मिला। दिल्ली सरकार ने अपने अधिकार बढ़ाकर बिजली बोर्ड बनाकर बिजली का उत्पादन बढ़ाया। नए स्कूल-कॉलेज ही नहीं, नया विश्वविद्यालय बनाया गया। नए अस्पताल बने और बड़ी संख्या में दिल्ली के हर कोने में निर्माण कार्य हुए। दिल्ली मेट्रो की नींव रखी गई। 1984 के सिख दंगा पीडितों को न्याय दिलाने के प्रयास हुए।

इस सिलसिले को साल 1998 में शीला दीक्षित की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने और आगे बढ़ाया। दिल्ली के मूलभूत ढांचे के विकसित करने की सर्वाधिक श्रेय शीला दीक्षित के जाता है। पूरी दिल्ली में काम हुए। दिल्ली फ्लाईओवर का शहर हो गया।फिर दस साल प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी(आआपा) की सरकार बनी।

उसके बाद सालभर पहले भाजपा की सरकार बनी। चुनाव प्रचार में भाजपा के नेताओं के वायदों में से कुछ पर तो अमल शुरू हो गए हैं लेकिन काफी काम अभी करने बाकी हैं। आआपा शासन के दस साल ने दिल्ली में विकास की दिशा ही बदल दी थी, जिसे वापस पटरी पर लाना भाजपा सरकार के लिए पहली चुनौती थी।

दिल्ली की समस्या अनोखी है। उसका इलाका तो 1483 किलोमीटर ही रहना है लेकिन आबादी बेहिसाब बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी में हर साल पांच लाख अतिरिक्त आबादी जुड़ती है। देश की राजधानी होने और नोट-वोट की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल इस पर अंकुश लगाना नहीं चाहता है। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है। मौसम से लेकर बिजली-पानी के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है। दिल्ली की सड़क भी एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ सकती। लोक निर्माण विभाग की 1400 किलोमीटर सड़कों में से पहले साल में 750 किलोमीटर सड़कों की वाल-टू-वाल कारपेंटिंग किया जाएगा। सड़कों पर आवागमन सुगम करने के लिए नए फ्लाईओवर और 40 नए फुट ओवरब्रिज का काम हो रहा है।

दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए वायु प्रदूषण शमन योजना बनाई गई है। सरकार का फोकस दिल्ली की साफ सफाई पर है, इसमें उसे काफी सफलता मिली। ओलंपिक आदि जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को बीस लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।

सरकार का दावा है कि दिल्ली में हर रोज निकलने वाले 11 हजार मीट्रिक टन कचरे का निबटान करने की व्यापक योजना बनने से कूड़े के नए पहाड़ बनेंगे। इतना ही नहीं कूड़े के पहाड़ों से भी दिल्ली को जल्दी ही निजात मिल जाएगी। सरकार ने फीस रेगुलेशन बिल विधानसभा में पास करके निजी स्कूलों पर लगाम लगाई। इस साल 44 करोड़ रुपए की छात्रवृति बांटी गई। इस सरकार के सामने यमुना को साफ करने की बड़ी चुनौती है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने यमुना की आरती शुरू करवाई और यमुना को साफ करने का संकल्प लिया।

रायबरेली के आलोक बने भारतीय पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान

एजेंसी

रायबरेली। एनटीपीसी ऊंचाहार में कार्यरत और रायबरेली निवासी आलोक शर्मा को भारतीय पैरा क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। श्रीलंका की फिजिकल क्रिकेट एसोसिएशन के निमंत्रण पर 3 से 5 अप्रैल 2026 तक कोलंबो के स्काई स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में भारत और श्रीलंका के बीच विशेष रूप से सक्षम (पैरा) खिलाड़ियों का टी-20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए आलोक शर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी इस उपलब्धि पर परियोजना के अधिकारियों कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि आलोक शर्मा भारतीय पैरा क्रिकेट टीम में पहले भी खिलाड़ी के तौर पर चयनित हो चुके हैं और उन्होंने कई मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। वह इससे पहले नवंबर 2025 में भी श्रीलंका में भारतीय पैरा क्रिकेट टीम की ओर से खेल चुके हैं।अब यह उनकी दूसरी अंतरराष्ट्रीय यात्रा होगी, जिसमें वे कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। डीएएफसी इंडिया के आयोजन सचिव महेंद्र सिंह द्वारा जारी चयन पत्र में आलोक शर्मा के समग्र प्रदर्शन के आधार पर उन्हें कप्तान चुने जाने की जानकारी दी गई है। चयन में सभी राज्यों के खिलाड़ियों और डीएएफसी अधिकारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा गया। आलोक शर्मा रायबरेली के जवाहर विहार कॉलोनी में रहते हैं और एनटीपीसी में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं।

बीसीसीआई : हाई परफार्मेंस कैंप के लिए हिमाचल के क्रिकेटर पुखराज मान का चयन

धर्मशाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से हाई परफार्मेंस कैंप फॉर इमरजिंग अंडर-25 पुरुष के लिए एचपीसीए के क्रिकेटर पुखराज मान का चयन हुआ है। यह कैंप 13 अप्रैल से 7 मई के बीच बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस में आयोजित होगा। कैंप का आयोजन 25 वर्ष से कम आयु के उभरते क्रिकेटरों के लिए किया जा रहा है। इस कैंप के लिए खिलाड़ियों को 12 अप्रैल को निर्धारित स्थान पर रिपोर्ट करना होगा। एचपीसीए सचिव मनुज शर्मा ने बताया कि एचपीसीए खिलाड़ी पुखराज मान का कैंप के लिए चयन होना खुशी की बात है। इस कैंप में शामिल होने से पहले, उक्त खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस का आकलन एचपीसीए द्वारा धर्मशाला स्थित क्रिकेट स्टेडियम में किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें कैंप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। एचपीसीए ने पुखराज मान को बधाई देते हुए आगामी कैंप के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

केआईटीजी 2026 (सातवां दिन राउंडअप) : झारखंड के शिव कुमार और पृथ्वी उरांव सबसे तेज धावक

रायपुर। झारखंड के शिव कुमार सोरेन और पृथ्वी उरांव ने जगदलपुर के क्रीड़ा परिसर मैदान में आयोजित किए जा रहे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में सबसे तेज धावक बनने का गौरव हासिल किया। वहीं, मेजबान छत्तीसगढ़ के सिद्धार्थ नागेश ने शॉट पुट में स्वर्ण और डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता, जबकि तिलक बारसेट ने पुरुष 100 मीटर में रजत पदक अपने नाम किया।शिव कुमार और पृथ्वी ने अपनी-अपनी 100 मीटर दौड़ की शुरुआत से अंत तक बढ़त बनाए रखते हुए अपने राज्य के लिए स्वर्ण पदक जीते। शिव कुमार ने 10.58 सेकंड का समय लिया, जबकि बारसेट ने 10.87 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। ओडिशा के अतिश किंडो (10.91 सेकंड) ने कांस्य पदक जीता। महिला 100 मीटर फाइनल में 16 वर्षीय पृथ्वी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 12.73 सेकंड में दौड़ पूरी कर स्वर्ण पदक जीता। नागालैंड की रुडुओल्हौनुओ बेल्हो (12.90 सेकंड) और झारखंड की पुतुल बक्शी (13.03 सेकंड) ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक हासिल किए।

टेबल टेनिस वर्ल्ड कप में मनिका ने नॉकआउट की उम्मीदें जिंदा रखीं, श्रीजा को पहले मुकाबले में मिली हार

मकाऊ (चीन)। आईटीटीएफ टेबल टेनिस वर्ल्ड कप में भारत की मनिका बत्रा ने शानदार वापसी करते हुए नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है, जबकि श्रीजा अकुला को अपने पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तीन बार की ओलंपियन मनिका बत्रा ने अमेरिका की लिली झांग को कड़े मुकाबले में 3-2 (11-7, 11-2, 14-16, 5-11, 11-6) से हराया। यह मुकाबला 43 मिनट तक चला। इससे पहले मनिका को अपने पहले मैच में जापान की मिवा हारिमोटो के खिलाफ 0-3 से हार झेलनी पड़ी थी। वहीं, विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर काबिज श्रीजा अकुला को अपने पहले मुकाबले में पुर्तगाल की फू यू के हाथों 1-3 (11-8, 9-11, 13-15, 8-11) से हार का सामना करना पड़ा। अब श्रीजा का अगला मुकाबला चीन की विश्व नंबर-2 वांग मान्यु से होगा। पुरुष वर्ग में भारत के एकमात्र खिलाड़ी मानव ठक्कर को अपने पहले मैच में कोरिया के पार्क गांगह्योन के खिलाफ 0-3 से हार मिली थी। अब उन्हें स्वीडन के ओलंपिक रजत पदक विजेता ट्रुल्स मोरेगार्ड के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला खेलना होगा।

अंबिकापुर : खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक की मनीषा जोंस सिद्दी ने जीता गोल्ड

एजेंसी

अंबिकापुर। 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' के प्रथम ऐतिहासिक संस्करण में कर्नाटक की बेटी मनीषा जोंस सिद्दी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए कुश्ती के 76 भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। अभावों के बीच पली-बढ़ी मनीषा की यह जीत केवल एक पदक नहीं, बल्कि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प की विजय है। मनीषा का खेल जीवन चुनौतियों से भरा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वह पाँचवीं कक्षा में थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इसके बावजूद, उनकी माँ ने हार नहीं मानी और अकेले दिन-रात मेहनत करके मनीषा के सपनों को पंख दिए। पूर्व में कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सिल्वर और ब्रोंज मेडल जीत चुकीं मनीषा के करियर का यह पहला गोल्ड मेडल है। अपनी

सफलता को साझा करते हुए मनीषा ने कर्नाटक के डिवाइस स्पोर्ट्स हॉस्टल की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'हॉस्टल के कोच और साथी खिलाड़ियों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। मेरा बड़ा भाई मेरा मार्गदर्शक रहा है, वहीं छोटा भाई, जो खुद एक राज्य स्तरीय एथलीट है, वह मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। मनीषा ने केंद्र सरकार और आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' जैसे मंच से जनजातीय समुदाय के बच्चों को अपनी विशेष पहचान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा मैच के दौरान सुरक्षा, भोजन और यातायात की व्यवस्था बेहतरीन थी। छत्तीसगढ़ के लोगों का व्यवहार और यहाँ का माहौल खिलाड़ियों के लिए अत्यंत सुखद है। स्वर्ण पदक की चमक के साथ मनीषा की निगाहें अब भविष्य की बड़ी चुनौतियों पर हैं। छत्तीसगढ़ की धरती पर मिली इस सफलता से उत्साहित मनीषा अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी में जुटी हैं। उनका अंतिम लक्ष्य विश्व पटल पर स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाना है।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स : हॉकी में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक

एजेंसी

रायपुर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आज बुधवार को रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में पुरुषों की हॉकी में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच तीसरे और चौथे स्थान के लिए मैच खेला गया। इसमें छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश को 14-6 से हरा कर कांस्य पदक जीता। मैच की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ की टीम आक्रामक नजर आई और लगातार गोल दागते हुए विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा। मध्यप्रदेश की टीम ने भी मुकाबले में वापसी की कोशिश की, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के बेहतरीन समन्वय और तेज खेल के आगे टिक नहीं पाई। शानदार जीत के साथ छत्तीसगढ़ की टीम ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया और स्टेडियम में मौजूद खेल प्रेमियों ने जोरदार तालियों के साथ टीम का उत्साहवर्धन किया। इस जीत के साथ छत्तीसगढ़ ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और राज्य के खिलाड़ियों के बढ़ते खेल कौशल को भी प्रदर्शित किया है।

वर्ल्ड कप से पहले ब्राज़ील की दमदार तैयारी, क्रोएशिया को 3-1 से हराया

एजेंसी

ऑरलैंडो। ब्राज़ील राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप की तैयारियों के तहत खेले गए मैत्री मुकाबले में क्रोएशिया राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को 3-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबला कैम्पिंग वर्ल्ड स्टेडियम में खेला गया।

मैच के पहले हाफ में ब्राज़ील ने गेंद पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा और कई मौके बनाए। 20वें मिनट में दानिलो का प्रयास क्रोएशियाई गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच ने रोक दिया। इसके बाद भी ब्राज़ील लगातार आक्रामक खेल दिखाता रहा। आखिरकार पहले हाफ के अंत में ब्राज़ील को सफलता मिली, जब माथियस कुन्हा के पास पर विनीसियस जूनियर ने बेहतरीन रन बनाते हुए दानिलो को पास दिया, जिन्होंने शानदार फिनिश के साथ टीम को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में क्रोएशिया ने वापसी की कोशिश की और 84वें मिनट में लोवरो माजेर ने टोनी फ्रुक के क्रॉस पर गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। हालांकि, इसके बाद ब्राज़ील ने तेजी से जवाब

दिया। 88वें मिनट में इगोर थियागो ने पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को फिर से बढ़त दिलाई। इंजरी टाइम में गेब्रियल मार्टिनेली ने गोल कर जीत 3-1 से पक्की कर दी।

मैच के बाद कैसेमिरो ने कहा कि टीम को अभी और सुधार की जरूरत है, लेकिन वे वर्ल्ड कप में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। अब ब्राज़ील जून में मिस्र राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के खिलाफ एक और अभ्यास मैच खेलेगा, जबकि वर्ल्ड कप में उसका पहला मुकाबला मोरक्को से होगा। वहीं, क्रोएशिया टूर्नामेंट से पहले बेल्जियम और स्लोवेनिया के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगा।

इटली लगातार तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप से बाहर, प्लेऑफ में बोस्निया से पेनल्टी शूटआउट में मिली हार

एजेंसी

जेनिका। चार बार की विश्व चैंपियन इटली राष्ट्रीय फुटबॉल टीम एक बार फिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रही है। यूरोपीय प्लेऑफ मुकाबले में इटली को 66वीं रैंकिंग वाली बोस्निया और हर्जेगोविना के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत में मोइज़ कीन ने गोल कर इटली को बढ़त दिलाई, लेकिन पहले हाफ में ही सेंटर-बैक अलेसांद्रो बास्तोनी को रेड कार्ड मिलने से टीम 10 खिलाड़ियों तक सिमट गई। इसका फायदा उठाते हुए बोस्निया के सब्स्टीट्यूट हारिस तबाकोविक ने 79वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया, जिससे मैच अतिरिक्त समय में चला गया। अतिरिक्त समय में भी कोई नतीजा नहीं निकल सका और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक पहुंचा, जहां इटली को हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही इटली लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गई है। इससे पहले टीम को पिछले दो वर्ल्ड कप क्वालीफायर प्लेऑफ में स्वीडन और नॉर्थ मैसिडोनिया के हाथों बाहर होना पड़ा था। 1934, 1938, 1982 और 2006 में खिताब जीत चुकी इटली अब कम से कम 16 साल तक वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेले बिना रह सकती है। टीम का खराब प्रदर्शन 2010 और 2014 वर्ल्ड कप से ही शुरू हो गया था, जहां वह ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी थी। हालांकि, इटली ने

2021 में यूरोपीय चैम्पियनशिप जीतकर वापसी की झलक जरूर दिखाई थी। इटली का आखिरी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच 2006 में था, जब उसने फाइनल में फ्रांस को हराकर खिताब जीता था। 1958 के बाद यह पहली बार है जब इटली इतनी बार वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने में असफल रही है, जिससे टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

आईपीएल 2026: पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया

एजेंसी

न्यू चंडीगढ़। आईपीएल 2026 का चौथा मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला गया। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराकर इस सीजन की शुरुआत जीत से की। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में डेब्यू मैच खेलने वाले सलामी बल्लेबाज कूपर कोनोली ने शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जिससे पंजाब किंग्स ने 19.1 ओवर में सात विकेट पर 165 बनाकर मैच जीत लिया। पंजाब किंग्स की स्थिति एक समय नाजुक हो गई थी, लेकिन कोनोली ने एक छोर से मोर्चा संभाला और टीम को जीत दिलाई। कोनोली 44 गेंदों पर पांच

चौकों और पांच छक्कों की मदद से 72 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, प्रभसिमरन सिंह ने 37 रन की पारी खेली। गुजरात के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन विकेट झटके, जबकि रबाडा, अशोक, राशिद और वाशिंगटन को एक-एक विकेट मिला। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 163 रनों का लक्ष्य दिया है। गुजरात ने 20 ओवर में छह विकेट पर 162 रन बनाए। गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान शुभमन गिल ने बनाए। उन्होंने 39 रनों की पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 38 रन बनाए। गुजरात ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन टीम इस लय को बरकरार नहीं रख सकी। आखिरी ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने 11 गेंदें की क्योंकि चार वाइड और एक नो बॉल फेंकी। पंजाब की ओर से विजयकुमार विशाक ने तीन विकेट, युजवेंद्र चहल ने दो विकेट और मार्को यानसेन ने एक विकेट झटके।

धीमी ओवर गति के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर लगा जुर्माना

एजेंसी

न्यू चंडीगढ़। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के तहत धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान की गई।

आईपीएल की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह जुर्माना लगाया गया, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम निर्धारित समय सीमा में अपने ओवर पूरे करने में विफल रही। पहले बल्लेबाजी पारी लगभग दो घंटे तक चली, जबकि नियमों के अनुसार 20वां ओवर डेढ़ घंटे के भीतर शुरू होना चाहिए। मैच के दौरान पंजाब किंग्स ने कुल 14 अतिरिक्त रन दिए, जिनमें 11 वाइड और एक नो-बॉल शामिल रही। इससे पारी और लंबी हो गई। इसके चलते टीम को अंतिम ओवर में अतिरिक्त फील्डर को इनर सर्कल के भीतर रखना पड़ा, जिससे रणनीति पर भी असर पड़ा।

आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल की नीलामी, सबसे महंगे 15 लाख में बिके आशुतोष शर्मा

एजेंसी

इंदौर। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग (एमपीएल) के आगामी सीजन के लिए इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। आईपीएल की दर्ज पर हुई इस नीलामी में आशुतोष शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। उन्हें मालवा स्टेलियंस ने 15 लाख रुपये में खरीदा है। वहीं, दूसरे नंबर पर अक्षत रघुवंशी हैं, जिन्हें रीवा जगुआर ने 13.80 लाख रुपये कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया। तीसरी सबसे बड़ी बोली अनिकेत वर्मा को मिली। अनिकेत को भोपाल लेपर्ड्स ने 13 लाख 20 हजार रुपये में खरीदा। शिवांग कुमार को बुंदेलखंड बुल्स ने 13 लाख कीमत देकर अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं, आवेश खान को चंबल घड़ियाल ने 8.20 लाख और शिवम शुक्ला को इंदौर पिंक पैंथर ने 6.60 लाख रुपये में खरीदा है।

इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ऑक्शनियर चारू शर्मा ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। नीलामी में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महानआर्यमान सिंधिया भी मौजूद रहे। इस नीलामी में सबसे पहले फ्रेंचाइजी टीमों की जानकारी दी गई। बताया गया कि पिछले संस्करण की सात टीमों ने अपने एक-एक आईकॉन खिलाड़ी को रिटेन किया है। इनमें सबसे महंगे वेंकटेश अय्यर हैं, जिन्हें पिंक पैंथर्स टीम ने 12 लाख 50 हजार रुपये में रिटेन किया। वे आरसीबी में रजत पाटीदार की कप्तानी में खेलते हैं, लेकिन रजत को ग्वालियर चीताज ने सात लाख रुपये में रिटेन किया है। उनसे महंगे अरशद खान हैं, जिन्हें भोपाल लेपर्ड्स ने आठ लाख रुपये में रिटेन किया है।

नीलामी में कुमार कार्तिकेय को 10.20 लाख रुपये में रॉयल निमाड़ ईगल्स, मंगेश यादव को 12 लाख रुपये में ग्वालियर चीताज, उज्जैन फाल्कन ने माधव तिवारी को 10.60 लाख, रॉयल निमाड़ ईगल्स ने सारांश जैन को 9.60 लाख और रीवा के कुलदीप सेन को 7 लाख में बुंदेलखंड बुल्स ने खरीदा। एमपीएल की इस नीलामी में शामिल सभी फ्रेंचाइजी को खिलाड़ियों की खरीद के लिए 50 लाख रुपए का पर्स आवंटित किया गया था। इस नीलामी प्रक्रिया में कुल 244 खिलाड़ियों ने अपनी किस्मत आजमाई। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो जून 2026 में इसके मुकाबले इंदौर और ग्वालियर के मैदानों पर खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह टूर्नामेंट प्रदेश के बेहतरीन टेलेंट को देखने का एक बड़ा मंच साबित होगा। इस बार एमपीएल में खिलाड़ियों की उम्र को लेकर एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को इस टी-20 टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति नहीं दी गई है।

सरगुजा में कुश्ती का दमदार समापन, हिमाचल और असम बने चैंपियन

एजेंसी

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले चार दिनों से चल रही कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन हो गया। देशभर से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबले देखने को मिले, जहां प्रतिभागियों ने अपनी तकनीक, ताकत और रणनीति का शानदार प्रदर्शन करते हुए पदकों पर कब्जा जमाया।समापन अवसर पर घोषित टीम चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में हिमाचल प्रदेश ओवरऑल चैंपियन रहा, जबकि जम्मू-कश्मीर ने फर्स्ट रनरअप और महाराष्ट्र व झारखंड ने संयुक्त रूप से सेकंड रनरअप का स्थान हासिल किया। वहीं महिला वर्ग में असम ने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि झारखंड फर्स्ट रनरअप और कर्नाटक व तेलंगाना सेकंड रनरअप रहे।

अंतिम दिन खेले गए मुकाबलों में महिला सीनियर 57 किलोग्राम वर्ग में तेलंगाना की नागलक्ष्मी ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि कर्नाटक की शालिनी सिद्धि को रजत और अमूल्या भीमसेन कुन्दरगी को कांस्य पदक मिला। महिला सीनियर 68 किलोग्राम वर्ग में कर्नाटक की प्रिंसिता पेड्र फर्नांडिस सिद्दी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मिजोरम की एलिजाबेथ रोहलुपुल्ल को रजत और गुजरात की चावड़ा लीलाबेन मैयाभाई तथा राजस्थान की बालकेश कुमारी मीना को कांस्य पदक मिला। पुरुष वर्ग के मुकाबलों में फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में ओडिशा के अजीत भुयां ने स्वर्ण, महाराष्ट्र के पारस सुभाष बिडकर ने रजत और महाराष्ट्र के विक्की रामचंद्र उइके व हिमाचल प्रदेश के अब्दुल खान ने कांस्य पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन 77 किलोग्राम वर्ग में झारखंड के अभिषेक मुंडा ने स्वर्ण, हिमाचल प्रदेश के अर्फन ने रजत और तेलंगाना के जादव चरण व जम्मू-कश्मीर के इंजमाम ने कांस्य पदक जीता।इसी तरह पुरुष फ्रीस्टाइल 86 किलोग्राम में हिमाचल प्रदेश के सुमित ठाकुर ने स्वर्ण, जम्मू-कश्मीर के बहादुर खान ने रजत और हिमाचल प्रदेश के शब्बीर खान ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

मेसी के गोल और असिस्ट से अर्जेंटीना की शानदार जीत, मैत्री मैच में जाम्बिया को 5-0 से हराया

एजेंसी

ब्यूनस आयर्स। लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अंतरराष्ट्रीय मैत्री मैच में जाम्बिया को 5-0 से करारी शिकस्त दी। यह मुकाबला ब्यूनस आयर्स के मशहूर ला बोम्बोनेरा स्टेडियम में खेला गया।

कोच लियोनेल स्कालोनी ने पिछले मैच में औसत प्रदर्शन के बाद मेसी को दोबारा प्लेइंग इलेवन में शामिल किया, और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। मैच के चौथे मिनट में ही मेसी ने शानदार पास देकर जूलियन अल्वारेज से पहला गोल करवाया। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले मेसी ने खुद भी गोल दागते हुए अंतरराष्ट्रीय करियर का 116वां गोल पूरा किया। उन्होंने एलेक्सिस मैक एलिस्टर के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गेंद को जाल में पहुंचाया। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली, लेकिन मेसी ने खुद शॉट लेने के बजाय गेंद निकोलस ओटामेंडी को सौंप दी, जिन्होंने इसे गोल में बदलकर स्कोर 3-0 कर दिया। इसके बाद जाम्बिया के डोमिनिक चांदा के आत्मघाती गोल से बढ़त 4-0 हो गई। अंत में युवा खिलाड़ी वैलेन्टिन बार्को ने इंजरी टाइम में गोल कर स्कोर 5-0 कर दिया। यह मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप से पहले घरेलू मैदान पर आखिरी मैच था। टीम जून में होने वाले टूर्नामेंट में अपने खिताब का बचाव करेगी।

कोच्चि में पहली जीत के साथ भारत का एशियन कप क्वालीफायर अभियान का शानदार समापन

एजेंसी

कोच्चि। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय टीम ने कोच्चि में अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए एएफसी एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वालीफायर (फाइनल राउंड) अभियान का शानदार अंत किया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने हांगकांग को 2-1 से हराया। डेब्यू कर रहे रयान विलियम्स और लेफ्ट-बैक आकाश मिश्रा के गोलों ने ब्लू टाइगर्स को इस क्वालीफाइंग अभियान की पहली जीत दिलाई। भारत ने अपने अभियान का समापन पांच अंकों (एक जीत, दो ड्रॉ और तीन हार) के साथ किया, जबकि सिंगापुर 14 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए एशियन कप के लिए क्वालीफाई कर गया। मुख्य कोच खालिद जमील ने रयान विलियम्स को डेब्यू का मौका दिया, जबकि बिजॉय वर्गीज़ ने भी सब्स्टीट्यूट के तौर पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। भारत ने मैच की शानदार शुरुआत की। चौथे ही मिनट में रयान विलियम्स ने अपने डेब्यू को यादगार बनाते हुए गोल दागा। अभिषेक सिंह टेकचाम के पास पर मनवीर सिंह ने गेंद को विलियम्स के लिए सेट किया, जिन्होंने आसान फिनिश के साथ भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह भारत के लिए किसी डेब्यू खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे तेज गोल भी रहा। बढ़त लेने के बाद भारत ने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा और आत्मविश्वास के साथ गेंद पर कब्जा रखते हुए खेल की गति तय की। मनवीर सिंह ने लालियानजुआला

छांगते के लिए एक शानदार क्रॉस भी दिया, लेकिन हांगकांग के डिफेंडर ने खतरे को टाल दिया। भारतीय डिफेंस ने हांगकांग को ज्यादा मौके नहीं दिए, और हर हमले को मजबूती से रोका। वहीं, भारत काउंटर अटैक में लगातार खतरनाक दिखा। 25वें मिनट में अपुइया (लालेंगमाविया) ने भी दूरी से शॉट लिया, जो थोड़ा सा बाहर निकल गया। दूसरे हाफ की शुरुआत भी भारत ने शानदार तरीके से की। 50वें मिनट में राहुल भेके के लंबे थ्रो के बाद बॉक्स में अफरातफरी मची, जहां आकाश मिश्रा ने तेजी दिखाते हुए नजदीकी कोण से गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। यह उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल था। हालांकि, 65वें मिनट में हांगकांग ने वापसी की। ब्राउनश्टाइन बराक के पास पर एवर्टन कैमार्गो ने शानदार फिनिश करते हुए अंतर को कम कर दिया। इसके बाद भारत ने खेल पर पकड़ बनाए रखी, जबकि कोच खालिद जमील ने रयान विलियम्स और अनवर अली की जगह आशीक कुरुनियान और जैकसन सिंह को उतारा। आशीक ने आते ही आक्रमण में नई ऊर्जा भर दी और लगातार मौके बनाए।

हांगकांग ने भी अंत में दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन गुरप्रीत सिंह संधू और भारतीय डिफेंस ने मजबूती से स्थिति संभाली। 90वें मिनट में बिजॉय वर्गीज़ को डेब्यू का मौका मिला और उन्होंने इंजरी टाइम में एक महत्वपूर्ण स्लाइडिंग टैकल कर गोल का खतरा टाल दिया। अंत में भारत ने 22,690 दर्शकों के सामने 2-1 की कड़ी जीत दर्ज की और कोच्चि में पहली जीत के साथ अपने अभियान का सकारात्मक अंत किया। भारतः गुरप्रीत सिंह संधू (जीके), राहुल भेके, अनवर अली (जैकसन सिंह थौनाओजाम 70'), संदीप झिंगन, आकाश मिश्रा (रोशन सिंह नाओरेम 84'), लालियानजुआला छांगते (बिजॉय वर्गीज़ 90'), लालेंगमाविया, मनवीर सिंह, रयान विलियम्स (आशीक कुरुनियान 70'), अभिषेक सिंह टेकचाम, लिस्टन कोलाको।

एफपीआई ने मार्च में की रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली

मुंबई। पश्चिम एशिया संकट और रुपये में जारी तेज गिरावट के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने मार्च में भारतीय पूंजी बाजार में करीब 1.27 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। शुद्ध बिकवाली उनके द्वारा लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है। केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा कंपनी सीडीएसएल के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने मार्च में पूंजी बाजार से कुल 1,26,991 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की जो अपने-आप में रिकॉर्ड है। कोरोना काल में मार्च 2020 के बाद यह पहला मौका है जब एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध निकासी की है। मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तब एफपीआई ने 1,18,203 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की थी। इक्विटी से एफपीआई ने मार्च में 1,17,775 करोड़ रुपये निकाले जिसका असर शेयर बाजारों पर साफ दिखा। महीने के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही।यह पहला मौका है जब एक ही महीने में इक्विटी में एफपीआई निवेश में एक लाख करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गयी है। डेट में उनकी शुद्ध बिकवाली 8,469 करोड़ रुपये और म्यूचुअल फंड में 2,616 करोड़ रुपये रही। हाइब्रिड उपकरणों में उन्होंने कुल 1,852 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।

एयरटेल की डाटा सेंटर कंपनी नेक्स्ट्रा में एक अरब डॉलर के निवेश की घोषणा

नई दिल्ली। दूरसंचार सेवा प्रदाता एयरटेल ने अपनी डाटा सेंटर कंपनी नेक्स्ट्रा में एक अरब डॉलर के निवेश की घोषणा है जिसका इस्तेमाल कंपनी के विस्तार और विकास को गति देने के लिए किया जायेगा। एयरटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि मुख्य निवेशक एल्फा वेव ग्लोबल होगा जो 43.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। कार्लाइल 24 करोड़ डॉलर और एंकरेज कैपिटल 3.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा। शेष राशि (29 करोड़ डॉलर) का निवेश खुद एयरटेल द्वारा किया जायेगा। अंतिम शेयर होल्डिंग अभी तय नहीं की गयी है, लेकिन एयरटेल ने कहा है कि वह नेक्स्ट्रा में अपनी नियंत्रक हिस्सेदारी बनाये रखेगी। इस सौदे को अभी भारतीय नियामकों से मंजूरी मिलनी शेष है।इस पूंजी का उपयोग नेक्स्ट्रा की विकास योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए किया जायेगा। कंपनी अपनी बुनियादी ढांचा क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के साथ अपनी सेवाओं के पोर्टफोलियो का विस्तार करने की भी योजना बना रही है ताकि देश में तेजी से बढ़ते डाटा सेंटर सेक्टर में कंपनियों और सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थानों की मांग के अनुरूप खुद को ढाला जा सके।

एमएसपी पर दलहन-तिलहन खरीद 7 अप्रैल से होगी शुरू - कृषि मंत्री शाही

लखनऊ। रबी सीजन 2026-27 में भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि चना, मसूर, सरसों की खरीद 7 अप्रैल से 30 जून तक की जाएगी। इस दौरान पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था, डीबीटी भुगतान और विस्तृत क्रय नेटवर्क के माध्यम से किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद की यह रणनीति किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है और 75 जनपदों में उर्वरकों की सप्लाई सुचारु रूप से हो रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। चने का एमएसपी 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 7000 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर का 8000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने फसलों की खरीद के स्पष्ट लक्ष्य तय किए हैं। उन्होंने कहा कि चने के लिए 2.24 लाख मीट्रिक टन, मसूर के लिए 6.77 लाख मीट्रिक टन, सरसों के लिए 5.30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बरेका ने रचा इतिहास : 572 रेल इंजनों का रिकॉर्ड निर्माण, अब तक का सर्वाधिक वार्षिक उत्पादन

वाराणसी। बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 572 रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन है, जिसने भारतीय रेल के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। महाप्रबंधक आशुतोष पंत के नेतृत्व में बरेका ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां 477 इंजनों का निर्माण हुआ था, वहीं इस वर्ष लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्मित 572 इंजनों में 558 आधुनिक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शामिल हैं। इनमें WAG-9 (401) मालगाड़ी के लिए और WAP-7 (143) यात्री ट्रेनों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा 14 'अमृत भारत' लोकोमोटिव भी बनाए गए। वहीं 10 डीजल इंजन मोजांबिक को निर्यात किए गए और 4 इंजन घरेलू ग्राहकों को दिए गए। रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 553 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लक्ष्य के मुकाबले बरेका ने 558 लोकोमोटिव का निर्माण कर लक्ष्य से भी आगे निकलने का रिकॉर्ड बनाया।

कैबिनेट मंजूरी के बाद पांच राज्यों को जल जीवन मिशन 2.0 के तहत 1,561 करोड़ रुपये जारी

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में ग्रामीण घरों तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत पांच राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए फंड जारी कर दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट से 10 मार्च को मंजूरी मिलने के बाद यह राशि राज्यों को आवश्यक अनुपालन शर्तें पूरी करने पर दी गई है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश को कुल 1,561.53 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को 792.93 करोड़, छत्तीसगढ़ को 536.53 करोड़, मध्य प्रदेश को 154.02 करोड़, ओडिशा को 65.31 करोड़ और महाराष्ट्र को 12.74 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए कुल 8.69 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 3.59 लाख करोड़ रुपये है। यह 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से 1.51 लाख करोड़ रुपये अधिक है। नया ढांचा सेवा वितरण आधारित मॉडल पर केंद्रित है, जिसमें स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फंड जारी करने से पहले कई अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होती हैं। इनमें सुधार आधारित एमओयू पर हस्ताक्षर, योजनाओं का 'सुजलाम भारत' जीआईएस लिंक्ड एसेट रजिस्ट्री में सत्यापन, तकनीकी अनुपालन प्रमाणपत्र, वित्तीय समायोजन और खर्च का मिलान शामिल है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने हाल ही में राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक कर मिशन के रोडमैप पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि जल राज्य का विषय है और मिशन की सफलता राज्यों की जवाबदेही पर निर्भर करती है। जल जीवन मिशन 2.0 का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक देश के सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल उपलब्ध कराना है। इसके लिए समयबद्ध योजनाएं, स्थायित्व और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि अब तक 12 राज्यों ने सुधार आधारित एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईरान युद्ध लंबा चला तो महंगे हो सकते हैं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर

एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण मेमोरी और चिपसेट की आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने लगी है और युद्ध लंबा चलने की स्थिति में मोबाइल फोन, कंप्यूटर और हर उस डिवास के दाम बढ़ सकते हैं, जिनमें इनका इस्तेमाल होता है। भारत में नोकिया इंडिया की प्रबंधक विभा मेहरा ने एक रिपोर्ट जारी करने के बाद संवाददाताओं के प्रश्नों के उत्तर में बताया कि युद्ध के कारण दूसरी चीजों के साथ मेमोरी और चिपसेट की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। अभी डिवाइसों की आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पर्याप्त इनवेंटरी उपलब्ध है, लेकिन युद्ध जारी रहा तो मध्यम अवधि (छह महीने से दो साल) में असर दिखने लगेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मेमोरी और चिपसेट के दाम बढ़ने लगे हैं। कुछ लोगों ने इनका भंडारण शुरू कर दिया है और दाम बढ़ा दिये हैं। ऐसे में तुरंत नहीं तो आने वाले कुछ समय में इसका असर जरूर दिखेगा इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स 2026 जारी करते हुए श्रीमती मेहरा ने कहा कि भारत में डाटा उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। पिछले पांच साल में 21.7 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ता हुआ कुल डाटा ट्रैफिक साल 2025 में 27.6 एग्जाबाइट मासिक पर पहुंच गया। वहीं प्रति यूजर औसत मासिक डाटा खपत 18.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ पिछले साल 31.1 जीबी पर रहा। उन्होंने बताया कि इस वृद्धि में 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए)का सबसे बड़ा योगदान रहा। कुल 5जी डाटा उपभोग में इसकी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक रही।

मध्य पूर्व में तनाव का असर! अमेरिका और यूएई में 72 प्रतिशत तक बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

एजेंसी

वाशिंगटन। मध्य पूर्व में तनाव का असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। इससे अमेरिका से लेकर खाड़ी देश यूएई में पेट्रोल-डीजल की कीमत में 72 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अमेरिका में गैसोलीन (पेट्रोल) की कीमतें बढ़कर 4 डॉलर (भारतीय रुपए में करीब 380 रुपए) प्रति गैलन (1 गैलन =3.8 लीटर) से अधिक हो गई हैं यह बीते तीन वर्षों में पहला मौका है, जब गैसोलीन के दाम इस स्तर के पार निकल गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, पूरे देश में गैसोलीन की औसत कीमत बढ़कर 4.018 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से गैसोलीन की कीमतों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका में डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है और दाम 5 डॉलर प्रति गैलन (करीब 475 रुपए प्रति गैलन) के पार निकल गया है। मध्य पूर्व में तनाव शुरू होने के बाद से कीमतों में

40 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। खाड़ी के देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) की फ्यूल प्राइस कमेटी ने कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी। नई कीमतों के मुताबिक, सुपर 98 पेट्रोल की कीमत लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 3.39 दिरहम प्रति लीटर (भारतीय रुपए में करीब 87 रुपए प्रति लीटर) हो गई है, जो कि पहले 2.59 दिरहम प्रति लीटर थी।

स्पेशल 95 पेट्रोल का दाम लगभग 32 प्रतिशत बढ़कर 3.28 दिरहम प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 2.48 दिरहम प्रति लीटर था।

यूएई में डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है और यह 72 प्रतिशत बढ़कर 4.69 दिरहम प्रति लीटर (करीब 120 रुपए प्रति लीटर) पर पहुंच गई हैं, जो कि पहले 2.72 दिरहम प्रति लीटर पर थी।

अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम एक महीने में 48 प्रतिशत बढ़ा है और फिलहाल 107.28 डॉलर प्रति बैरल पर है।

इंडिगो ने आईएटीए के महानिदेशक विलियम वॉल्श को नियुक्त किया सीईओ

एजेंसी

नई दिल्ली। इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड ने विलियम वॉल्श को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है, हालांकि यह नियुक्ति नियामकीय मंजूरी के अधीन है। इससे पहले इसी महीने पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि वॉल्श का कार्यकाल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) में 31 जुलाई 2026 को समाप्त होगा और वह 3 अगस्त 2026 तक इंडिगो से जुड़ सकते हैं। विलियम वॉल्श, जिन्हें 'विली' के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में आईएटीए के डायरेक्टर जनरल हैं। इससे पहले वह ब्रिटिश एयरवेज और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप (आईएजी) के सीईओ रह चुके हैं, जिसमें एर लिंगस, इबेरिया, लेवल और वुएलिंग जैसी एयरलाइंस शामिल हैं।

इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने कहा कि बड़े स्तर पर एयरलाइन संचालन का अनुभव और

जटिल बाजार स्थितियों को संभालने की क्षमता वॉल्श को इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में एल्बर्स ने इस्तीफा दिया था। उन्होंने करीब तीन साल तक इंडिगो का नेतृत्व किया और इस दौरान एयरलाइन ने तेजी से विकास भी किया, हालांकि दिसंबर में कंपनी को अपने सबसे बड़े फ्लाइट संकट का सामना करना पड़ा था।

इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया ने कहा कि कंपनी अब बदलाव और विकास के नए दौर में प्रवेश कर रही है और ऐसे समय में वॉल्श का जुड़ना महत्वपूर्ण है।

अपने नए पद पर वॉल्श एयरलाइन के पूरे संचालन और रणनीतिक दिशा के लिए जिम्मेदार होंगे। उनका फोकस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत करने, नेटवर्क और कमर्शियल रणनीति को आगे बढ़ाने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर रहेगा।

वॉल्श ने कहा कि एविएशन सेक्टर तेजी से बदल रहा है और इंडिगो इस बदलाव में अग्रणी भूमिका निभाने की स्थिति में है। उन्होंने संगठन के साथ मिलकर उत्कृष्टता, नवाचार और सहयोग की संस्कृति को मजबूत करने की बात कही।

मार्च में 3.1 लाख पीएनजी कनेक्शनों का गैसीफाइड किया गयाः पेट्रोलियम मंत्रालय

एजेंसी

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरान युद्ध के कारण एलपीजी आयात में आई बाधाओं के बीच कुकिंग गैस की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। इस क्रम में मार्च में घरेलू, कमर्शियल, छात्रावास, और कैंटीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 3.1 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसीफाइड किया गया है, जबकि 2.7 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं और उनको गैसीफाइड किया जा रहा है। 1 मार्च, 2026 से औसतन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं, और एलपीजी वितरकों में किसी भी प्रकार की कमी की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा, मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 23 मार्च से प्रवासी श्रमिकों को 3.2 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं, जिनमें से सोमवार को 63,000 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और वाहनों के लिए सीएनजी के मामले में, मांग को पूरा करने के लिए

100 प्रतिशत आपूर्ति वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। ग्रिड से जुड़े औद्योगिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं को आपूर्ति उनकी औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत पर बनाए रखी जा रही है। बयान में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के मद्देनजर, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है, जबकि स्थानीय खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है। देश भर में सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अफवाहों के कारण घबराहट में खरीदारी के मामले देखे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप खुदरा दुकानों पर असामान्य रूप से अधिक बिक्री और भीड़भाड़ हुई है। हालांकि, बयान में कहा गया है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

सरकार ने जनता को अफवाहों पर विश्वास न करने की सलाह दोहराई है और राज्य सरकारों से प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से सही जानकारी प्रसारित करने का अनुरोध किया है। ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी फरवरी 2026 में 53 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 83 प्रतिशत हो गई है, जिससे हेराफेरी को रोकने में मदद मिली है।

किशनगंज एसडीपीओ गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, आय से 1.94 करोड़ अधिक संपत्ति का आरोप

एजेंसी

किशनगंज। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने किशनगंज के एसडीपीओ-वन गौतम कुमार के बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक स्थित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई किशनगंज के अलावा पूर्णिया, अररिया, पटना और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में की जा रही है। किशनगंज में ईओयू की टीम मंगलवार सुबह करीब आठ बजे तीन वाहनों से एसडीपीओ गौतम कुमार के आवास और कार्यालय पहुंची। टीम में करीब 12 अधिकारी शामिल हैं, जो दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य महत्वपूर्ण सामानों की जांच कर रहे हैं।

छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने एसडीपीओ गौतम कुमार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। प्रारंभिक जांच में करीब 1 करोड़ 94 लाख रुपये की अवैध संपत्ति का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जांच टीम संपत्ति से जुड़े बैंक दस्तावेज, जमीन खरीद-बिक्री के कागजात और अन्य वित्तीय लेन-देन की पड़ताल कर रही है। गौतम कुमार का पुश्तैनी घर सहरसा में है, जबकि पटना में भी उनका मकान है। वहीं पूर्णिया में उनका ससुराल बताया जा रहा है। इन सभी स्थानों पर भी जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान गौतम कुमार फिलहाल किशनगंज में ही मौजूद बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि हाल के दिनों में गौतम कुमार ने किशनगंज जिले में अवैध बालू खनन, लॉटरी माफिया, तस्करी और लूट के कई मामलों में कार्रवाई की थी, जिसमें कई बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ किया गया था। दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई को उनके खिलाफ कथित काली कमाई और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी।

पीएम ई-ड्राइव योजना से राजस्थान में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा विस्तार

एजेंसी

जयपुर। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपभोक्ताओं के लिए नई सौगात लेकर आई है। भारत सरकार ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) हेतु पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 81.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे राज्य में ईवी चार्जिंग के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान देश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य में ग्रीन एनर्जी नेटवर्क का विस्तार करते हुए इसे और प्रभावी बनाने की दिशा में

निरंतर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत प्रदेश में नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत सरकार के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। केन्द्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलने, राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और ईवी के उपभोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वीकृत योजना के अनुसार जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39 तथा कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ईवी उपयोगकर्ताओं को सुविधा मिलेगी। ये सभी चार्जिंग स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों की उपलब्ध भूमि पर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

इस पहल से राज्य में प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और स्वच्छ, हरित ऊर्जा को आमजन तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

शंघाई में हुई भारत-चीन बिजनेस राउंडटेबल, सतत सहयोग व नए व्यापारिक अवसरों हुई पर चर्चा

एजेंसी

शंघाई। चीन के शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के कॉर्पोरेट प्रतिनिधिमंडल के साथ एक उच्चस्तरीय बिजनेस राउंडटेबल का आयोजन किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करना और भारत-चीन के बीच सतत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की तेज आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला और कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। उन्होंने युवा जनसंख्या को भारत के लिए एक बड़ी ताकत बताते हुए अंतरराष्ट्रीय निवेश और साझेदारी के व्यापक अवसरों का जिक्र किया। माथुर ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचा विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को 'सनराइज सेक्टर' करार दिया। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में भारतीय और वैश्विक कंपनियों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। पीएचडीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा विशेष रूप से शंघाई, झेजियांग और जियांगसू प्रांतों की प्रमुख कंपनियों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बैठक में तकनीकी साझेदारी, बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें और नए व्यापारिक समझौतों पर विशेष जोर दिया गया। इस पहल से भारत की घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को गति मिलने की उम्मीद है। राउंडटेबल में चीनी पक्ष की ओर से उच्चस्तरीय भागीदारी देखी गई। एचएसबीसी और डब्ल्यूयूएक्सआई टेक्नोलाजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन समेत पूर्वी चीन की कई प्रमुख कंपनियों और वित्तीय संस्थानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन कंपनियों ने भारत के उभरते उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की।

केंद्र का राजकोषीय घाटा फरवरी तक लक्ष्य के 80 प्रतिशत पर

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 11 महीने में फरवरी 2026 तक पूरे वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत को पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 27,91,943 करोड़ रुपये रही, जो संशोधित अनुमान का 82 प्रतिशत है। इस दौरान कुल व्यय 40,44,592 करोड़ रुपये रहा जो संशोधित अनुमान का 81.5 प्रतिशत है। इस प्रकार, राजकोषीय घाटा 12,52,649 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह संशोधित अनुमान का 80.38 प्रतिशत है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 15,68,936 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया था जिसे बाद में संशोधित कर 15,58,492 करोड़ रुपये कर दिया गया। कुल प्राप्तियों में 21,45,223 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 5,81,173 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 65,547 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को करों के हिस्से के हस्तांतरण के तौर पर 12,66,369 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि की तुलना में 85,837 करोड़ रुपये अधिक है। कुल व्यय में 31,15,270 करोड़ रुपये राजस्व मद पर और 9,29,322 करोड़ रुपये पूंजी मद पर खर्च किये गये हैं।

नया आयकर कानून एवं कई बजटीय प्रावधान एक अप्रैल से लागू

एजेंसी

नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही एक अप्रैल से देश का आयकर ढांचा भी बड़े बदलावों के दौर में प्रवेश करने जा रहा है। नया आयकर अधिनियम, 2025 बुधवार से लागू हो जाएगा, जो करीब छह दशक पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। इस नए कानून के तहत टैक्स सिस्टम, प्रक्रियाओं और नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव वित्तीय वर्ष और निर्धारण वर्ष की जगह एकल 'कर वर्ष' की शुरुआत है, जिससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। आयकर विभाग के मुताबिक नए आयकर कानून और अन्य बजटीय प्रावधान 1 अप्रैल से लागू । इन बजटीय प्रावधान में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) व्यापार पर उच्च प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और चिकित्सा तथा शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी पर्यटन पैकेज एवं एलआरएस प्रेषणों पर कम टीसीएस शामिल हैं। इसके अलावा भारत में डेटा सेंटर सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक 20 वर्ष की कर छूट और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए 'सेफ हार्बर' प्रावधानों की सीमा बढ़ाने से संबंधित बजट घोषणाएं भी वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ बुधवार से प्रभावी हो जाएंगी। नए कानून का उद्देश्य उसी कर नीति को अधिक तार्किक, सुलभ एवं पाठक-अनुकूल प्रारूप में प्रस्तुत करना है। बदलाव अवधि के दौरान उसका ई-फाइलिंग मंच पुराने और नए दोनों आयकर कानूनों के तहत अनुपालन की सुविधा देगा। साथ ही पिछले वर्षों से संबंधित सभी आकलन, अपील एवं अन्य कार्यवाही अंतिम निपटान तक पुराने कानून के तहत ही जारी रहेंगी। आकलन वर्ष 2026-27 (जो पुराने कानून की अवधि से संबंधित है) के लिए जुलाई में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता पुराने कानून के तहत निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग करेंगे। कर वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर भुगतान जून से शुरू होगा। आयकर अधिनियम, 2025 में आकलन वर्ष और पूर्व वर्ष के अंतर को समाप्त कर एकल 'कर वर्ष' व्यवस्था लागू की गई है।

इसके साथ ही समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल होने पर भी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की वापसी बिना किसी दंड शुल्क के लेने की अनुमति दी गई है। एक अप्रैल से लागू होने वाला एक अन्य बड़ा बदलाव वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सौदों पर एसटीटी में वृद्धि है। वायदा अनुबंधों पर एसटीटी 0.02 फीसदी से बढ़कर 0.05 फीसदी हो जाएगा। विकल्प प्रीमियम एवं विकल्प के प्रयोग पर एसटीटी क्रमशः 0.1 फीसदी और 0.125 फीसदी से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो जाएगा। एसटीटी में यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजार के एफएंडओ खंड में सट्टेबाजी को सीमित करने और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान से बचाने के उद्देश्य से की गई है।आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी डेरिवेटिव (एफएंडओ) खंड में कारोबार करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या 2024-25 में 1.06 करोड़ थी, जो 2025-26 में (30 दिसंबर 2025 तक) घटकर लगभग 75.43 लाख रह गई। सेबी के अध्ययन 'इक्विटी डेरिवेटिव खंड में वृद्धि बनाम नकद बाजार' के अनुसार, 2024-25 में व्यक्तिगत निवेशकों को 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध नुकसान हुआ। इसके साथ ही आईटी सेवाओं के लिए 'सेफ हार्बर' सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे आईटी/आईटीईएस क्षेत्र को अधिक निश्चितता मिलेगी एवं मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है। आईटी सेवाओं के लिए 'सेफ हार्बर' एक कर व्यवस्था है जो ''ट्रांसफर प्राइसिंग'' विवादों को कम करने के लिए बनाई गई है। विदेशी यात्रा पैकेज और उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) में कमी का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना है।

अमेरिका कुछ हफ्तों में ईरान ऑपरेशन कर देगा खत्मः मार्को रुबियो

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिकी सरकार की तरह से बार-बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि वह लक्ष्य पूरा करने में तय समय से आगे चल रहे हैं और जल्द ही खत्म कर देंगे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि वह ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य महीनों में नहीं, बल्कि हफ्तों में पूरा कर लेगा। इस बीच अमेरिकी विदेश सचिव ने लड़ाई खत्म करने के लिए वाशिंगटन की शर्तें बताईं और तेहरान को होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करने की कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। स्थानीय समयानुसार, सोमवार को अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा कि सैन्य ऑपरेशन जारी रहने के बावजूद, 'ईरान और अमेरिका के अंदर कुछ लोगों के बीच खासकर बिचौलियों के जरिए मैसेज और कुछ सीधी बातचीत चल रही थी।' 'उन्होंने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन की मुख्य मांगें वैसी ही हैं, 'ईरानी सरकार के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते और उन्हें आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद करना होगा और उन्हें ऐसे हथियार बनाना बंद करना होगा जो उनके पड़ोसियों के लिए खतरा बन सकते हैं।'

इजरायल ने घातक हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा का कानून किया पारित

तेल अवीव । इजरायल की संसद ने एक विवादास्पद कानून पारित किया है, जिसके तहत सैन्य अदालतों द्वारा घातक हमलों के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा अनिवार्य कर दी गई है। यह कानून प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों की एक प्रमुख मांग में शामिल था। इस कानून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हुई है। विरोधियों ने इसे भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया है। आलोचकों का तर्क है कि यह कानून पहचान के आधार पर एक अलग कानूनी ढांचा तैयार करता है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। नए कानून के तहत, हत्या के दोषी पाए गए इजरायलियों को मृत्युदंड तभी दिया जाएगा, जब यह कृत्य 'इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने' के इरादे से किया गया हो।आलोचकों का कहना है कि यह प्रावधान प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करता है कि यह सजा असमान रूप से फिलिस्तीनियों को निशाना बनाएगी जबकि इसी तरह के अपराधों के आरोपी यहूदी इजरायलियों को इससे बाहर रखा जाएगा। कानून में यह भी अनिवार्य है कि फांसी की सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही दी जाए, जिसमें देरी के लिए केवल सीमित आधार दिए गए हैं और क्षमादान का कोई प्रावधान नहीं है। अदालतों के पास आजीवन कारावास की सजा देने का विकल्प बरकरार है लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा।

लेबनान में यूएन शांतिसैनिकों पर हमलाः फ्रांस के विदेश मंत्री ने की इजरायल की कड़े शब्दों में निंदा

पेरिस। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बारो ने इजरायल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लेबनान के नकौरा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना (यूएनआईएफआईएल) के साथ 'गंभीर घटनाएं' हुई हैं। बारो ने कहा कि इजरायली सैनिकों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों के साथ सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करना और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर फ्रांस ने पेरिस में मौजूद इजरायल के राजदूत के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बैरो ने रविवार को हुई गोलीबारी की भी 'कड़े से कड़े शब्दों' में निंदा की जिसमें इंडोनेशिया के एक शांति सैनिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इसके अलावा सोमवार को हुए एक धमाके में दो इंडोनेशियाई शांति सैनिकों की मौत और दो अन्य के घायल होने की घटना को भी उन्होंने बेहद गंभीर बताया। इन घटनाओं के बाद बारो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का सम्मान करें और संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनआईएफआईएल को अपना काम पूरी तरह से करने और बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही की अनुमति मिलनी चाहिए।

लीबिया से ग्रीस जा रही प्रवासियों की नाव समुद्र में रास्ता भटकी, 22 की मौत

ढाका। लीबिया से ग्रीस जा रही प्रवासियों की नाव समुद्र में रास्ता भटक गई। इस दौरान 22 लोगों की मौत हो गई। इनमें 12 युवा बांग्लादेश के नागरिक हैं। सुनामगंज के उपायुक्त मोहम्मद इलियास मिया ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस घटना के लिए जिम्मेदार मानव तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज करेगा। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सुनामगंज के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजन सरकार ने बताया कि

अब तक उन्होंने 12 नागरिकों की मौत की पुष्टि कर ली है। इनमें से छह लोग डेराई उपजिला के, पांच लोग जगन्नाथपुर उपजिला के और एक व्यक्ति दोराबाजार उपजिला का रहने वाला है। सुनामगंज के उपायुक्त मोहम्मद इलियास ने कहा कि इनके शव समुद्र से मिल गए हैं। 28 मार्च को बचाए गए 26 लोगों को ग्रीस के एक शिविर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस, परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और स्थानीय प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद अब तक 12 मृतकों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है।

ईरानी राष्ट्रपति ने इराक के लोगों का जताया आभार, बोले 'साझी लड़ाई में आपका साथ मददगार'

एजेंसी

तेहरान । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युद्ध के दौरान समर्थन देने पर इराकी लोगों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इराकी जनता इस संघर्ष में मजबूती से ईरान के साथ खड़ी रही। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि इराक ने इस अन्यायपूर्ण संघर्ष में ईरान के साथ पूरी हिम्मत से कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। यह समर्थन केवल भौगोलिक कारणों से नहीं, बल्कि साझा इतिहास, पहचान और धार्मिक मूल्यों की वजह से है। शनिवार और रविवार को ईरानी और इराकी मीडिया आउटलेट्स की ओर से ऑनलाइन साझा किए गए फुटेज में, हशद अल-शाबी, जिसे ईरान-समर्थित लड़ाकों के 'पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस' (पीएमएफ) नाम से भी जाना जाता है, का एक काफिला ईरान में प्रवेश करते हुए दिखाई दिया। ईरानी मीडिया ने इसे 'इराक के लोगों की ओर से मानवीय सहायता का पहला काफिला' करार

दिया था। हाल ही में इस संघर्ष में इराक भी शामिल हो गया। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले शुरू होने के बाद से ही, देश में हिंसा की वजह से अब तक 10-12 लोगों की जान जा चुकी है। पीएमएफ से जुड़े ईरान समर्थक गुट ने–जो सरकार के अंदर और बाहर, दोनों जगह काम करता है–बगदाद में अमेरिकी दूतावास, इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के ठिकानों, और इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिका से जुड़े स्थलों (जैसे कि होटलों) पर ड्रोन और रॉकेट से हमले किए हैं। पिछले हफ्ते, पीएमएफ ने दावा किया था कि एक इराकी सैन्य ठिकाने और पीएमएफ मुख्यालय पर हुए हमलों के लिए वाशिंगटन ही जिम्मेदार था, और इन हमलों में इराकी सुरक्षा अधिकारियों की जान चली गई थी। इस तरह के हमले–भले ही वे ईरान-समर्थक पीएमएफ गुटों को निशाना बनाकर किए गए हों–लेकिन इराकी सेना और पीएमएफ के बीच आपसी तालमेल और करीबी सहयोग को देखते हुए, इनसे इराकी सैनिकों की मौत होना तय है। हालांकि वाशिंगटन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, फिर भी इराक के प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे अमेरिकी दूतावास के 'चार्ज डी अफेयर्स' (कार्यवाहक राजदूत) को तलब करें।

पाकिस्तानः बलूचिस्तान में सुरक्षाकर्मियों पर हमला, तीन की मौत और चार घायल

एजेंसी

क्वेटा । अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दो अलग-अलग हमलों में तीन सुरक्षाकर्मी मारे गए और चार घायल हो गए। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। एक हमला क्वेटा में पेट्रोलिंग स्क्वॉड पर और दूसरा झाल मगसी स्थित पुलिस स्टेशन पर हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार शाम को क्वेटा के ईस्टर्न बाईपास इलाके में मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के ईगल स्क्वॉड के दो लोगों पर हमला हुआ, जिसमें तीन लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने ऑटोमैटिक हथियारों से सुरक्षाकर्मियों पर गोलियां चलाईं। पाकिस्तान के जाने-माने अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। झाल मगसी जिले के गंडावाह इलाके में कोटरा पुलिस स्टेशन को हथियारबंद लोगों ने निशाना बनाया। भाग रहे हमलावरों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद एक सुरक्षाकर्मी मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए। गंडावाह के कोटरा पुलिस स्टेशन के एसएसपी रहमतुल्लाह ने कहा कि हमलावरों ने रॉकेट और दूसरे भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संभावित हमले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर थी। यह घटना पाकिस्तान में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती प्रांतों में कानून लागू करने वाले कर्मचारियों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में बढ़ोतरी के बीच हुई। पुलिस के मुताबिक, 18 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले के गंदीगर के मनो बंदा इलाके में एलीट फोर्स के एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को अनजान बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी।

होर्मुज को लेकर ट्रंप की धमकियों के बाद कुवैती तेल से लदे टैंकर पर ईरान ने ड्रोन से किया हमला

एजेंसी

कुवैत। ईरान ने कुवैत के एक तेल टैंकर पर हमला किया है। इस हमले की पुष्टि कुवैत के लोगों ने की है। दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया कि इस हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही दुबई के पानी में तेल से भरे टैंकर पर हमले के बाद किसी लीक या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से नहीं खोला गया तो वे उसकी तेल फैसिलिटी को उड़ा देंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद ही कुवैती तेल टैंकर पर हमले की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, ट्रंप की धमकी को लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी सेना हमेशा कानून का पालन करेगी। इस बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना एक युद्ध अपराध हो सकता है। दुबई के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रिस्पॉन्स

टीमों ने दुबई के पानी में कुवैती तेल टैंकर से जुड़ी घटना को सफलतापूर्वक काबू कर लिया है, जिसमें कोई लीक नहीं हुआ और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। इससे पहले, कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी कूना ने बताया दुबई के पास खड़े बड़े क्रूड कैरियर अल-सलमी पर ईरानी सेना ने हमला किया था। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने तेल लीक की संभावना की चेतावनी दी थी। ब्रिटेन की मैरीटाइम अथॉरिटी (यूकेएमटीओ) के मुताबिक, जहाज दुबई से 31 नॉटिकल मील उत्तर-पश्चिम में हमले का शिकार हुआ था। इस हमले से जहाज में आग लग गई, जिसे बाद में दुबई के अधिकारियों ने बुझा दिया। अधिकारियों ने बताया कि अब आग पर काबू पा लिया गया है।

दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका-इजरायल से ईरान के खिलाफ जारी हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई बंद कर शांति बनाए रखने का अनुरोध करता है। इसके साथ ही चीन ने परमाणु संयंत्रों और 133 ऐतिहासिक स्थलों को पहुंचे नुकसान को भी अफसोसनाक बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस ब्रीफिंग में सरकार का पक्ष रखा।

ईंधन की बढ़ती कीमतों पर न्यूजीलैंड सरकार ने जरूरतमंदों को दी राहत, 1.43 लाख परिवारों को हर हफ्ते 50 डॉलर की अतिरिक्त मदद

एजेंसी

वेलिंगटन । अमेरिका-ईरान के बीच जारी संघर्ष का असर तेल की कीमतों पर साफ दिख रहा है। बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी सरकार द्वारा दी जा रही लक्षित महंगाई राहत का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, उनकी मदद करना जरूरी है। पीएम लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से न्यूजीलैंड में पेट्रोल पंप पर कीमतें सीधे तौर पर बढ़ रही हैं। इससे पूरे देश में घरों और बिजनेस पर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार सभी के लिए दबाव कम करने का जोखिम नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार को कोविड की गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए, जहां ज्यादा खर्च से महंगाई और ज्यादा कर्ज हुआ था। लक्सन ने कहा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा

जरूरत है, उन्हें समय पर सीमित अवधि के लिए और लक्षित सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सभी के लिए एक जैसे उपाय अपनाने से महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है।

लक्सन सरकार ने इन-वर्क टैक्स क्रेडिट को कुछ समय के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे अप्रैल की शुरुआत से लगभग 143,000 कम और मिडिल-इनकम वाले काम करने वाले परिवारों को हर हफ्ते एक्स्ट्रा 50 डॉलर मिलेंगे, ताकि वे बढ़ते फ्यूल के खर्चों में मदद कर सकें। यह मदद एक साल तक या पेट्रोल की कीमतें कम होने तक चलेगी और इससे लगभग 14,000 और परिवारों को कम रेट पर उपलब्धता मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि इन-वर्क टैक्स क्रेडिट में बढ़ोतरी का मकसद महंगाई या कर्ज बढ़ाए बिना ज्यादा खर्चों के असर को कम करना है। इस बड़े पैकेज के तहत, न्यूजीलैंड के दस लाख से ज्यादा लोगों को मौजूदा सरकारी मदद पेमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी। लगभग 10 लाख पेंशनभोगी को बढ़ा हुआ न्यूजीलैंड पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसमें शादीशुदा जोड़े का हर दो हफ्ते का पेमेंट 50 डॉलर से ज्यादा बढ़ जाएगा।

ईरान के लोग हवाई हमलों और जरूरी अपडेट को ट्रैक करने के लिए इस ऐप का कर रहे इस्तेमाल

एजेंसी

तेहरान । ईरान में 30 दिनों से ज्यादा समय तक इंटरनेट बंद है। ईरानी लोग हवाई हमलों और जरूरी अपडेट को ट्रैक करने के लिए अलग मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया सीएनएन ने बताया कि ईरान के लोग टेलीग्राम के जरिए एक-दूसरे के साथ मैसेजिंग या जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशियाई मीडिया आउटलेट ने बताया है कि ईरान के लोग एयरस्ट्राइक और अन्य जरूरी जानकारी के लिए माहसा अलर्ट ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएनए ने कहा बताया कि ईरान में हजारों लोग जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर लोग जानकारी साझा कर रहे हैं कि एयरस्ट्राइक कहां हुए, किन इलाकों में बिजली चली गई और कितना नुकसान हुआ। ईरान में होने वाले एयरस्ट्राइक के लिए कोई ऑफिशियल चेतावनी सिस्टम न होने के कारण, इसके नागरिक खुद ही समस्या का समाधान कर रहे हैं।

ईरानी नागरिक अपना खुद का क्राउडसोर्स्ड एयर अटैक वॉर्निंग सिस्टम बनाते हैं। इंडोनेशया के डिजिटल मीडिया पोर्टल वीओआई के अनुसार, ईरान में जब मिलिट्री हमलों या मूवमेंट से जुड़ी पब्लिक वॉर्निंग देने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी सिस्टम नहीं था, तब महसा अलर्ट नाम का प्लेटफॉर्म एक इमरजेंसी सॉल्यूशन के तौर पर सामने आया है। ईरान के डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने इस ऐप को तैयार किया है। यह ऐप हमलों और सैन्य गतिविधियों के स्थानों को मैप करने के लिए जनता, सोशल मीडिया और मैनुअल सत्यापन से प्राप्त डेटा पर आधारित है।

ऑफिशियल मिलिट्री वॉर्निंग सिस्टम के उलट, महसा अलर्ट पूरी तरह से रियल-टाइम नहीं है। हालांकि, यह एप्लिकेशन हमलों या खतरों से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी होने पर भी नोटिफिकेशन भेजता है।

हर डेटा अपडेट बहुत छोटा रखा जाता है, एवरेज सिर्फ 100केबी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कनेक्शन अनस्टेबल या लिमिटेड होने पर भी यूजर्स जानकारी हासिल कर सकें। इंडोनेशियाई न्यूज पोर्टल ने बताया कि सही जानकारी बनाए रखने के लिए, महसा अलर्ट के पीछे की टीम डेटा दिखाने से पहले अच्छी तरह वेरिफिकेशन करती है। पुष्टि के तौर पर मार्क की गई अटैक लोकेशन को सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो या इमेज-बेस्ड जांच से गुजरना होगा।

जरूरी मिनरल्स में चीन के दबदबे ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता, समुद्र तल पर माइनिंग को लेकर चर्चा शुरू

एजेंसी

वाशिंगटन । जरूरी मिनरल्स में चीन के दबदबे को लेकर अमेरिका की चिंता काफी बढ़ गई है। यही वजह है कि अमेरिका की दिलचस्पी गहरे समुद्र में माइनिंग में फिर से बढ़ रही है। हालांकि, विशेषज्ञों ने कानून बनाने वालों को चेतावनी दी है कि लहरों के नीचे के इकोलॉजिकल रिस्क को अभी भी ठीक से समझा नहीं गया है। कांग्रेस की सुनवाई में सीनेटरों और इंडस्ट्री के नेताओं ने कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे मिनरल्स के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया, जो डिफेंस सिस्टम, क्लीन एनर्जी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। कांग्रेस के सदस्य स्कॉट फ्रैंकलिन ने कहा कि ये संसाधन हमारे देश भर की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हैं और चेतावनी दी कि चीन जैसे दुश्मन बेशक अमेरिका को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री के अधिकारियों ने तर्क दिया कि अमेरिका के पास आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दोनों हैं। द मेटल्स कंपनी के सीईओ जेरार्ड बैरन ने लॉमेकर्स से कहा कि 'हम रिस्क को मैनेज करने के लिए काफी कुछ जानते हैं।' इस दौरान उन्होंने दशकों की रिसर्च और हाल की तरक्की की ओर इशारा किया, जो एनवायरनमेंटल डिस्टर्बेंस को कम करती हैं। बैरन ने कहा कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद खनिज गांठें अमेरिका की आयात पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि इनमें ऐसे धातु पाए जाते हैं जो रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए बेहद अहम हैं।

होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो भी ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने को तैयार हैंः अमेरिकी मीडिया

एजेंसी

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष रोकने के लिए हामी भरी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप सरकार के अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति ने अपने साथियों से कहा है कि वह ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, भले ही होर्मुज स्ट्रेट काफी हद तक बंद रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों का मानना है कि दुनिया के लिए ज़रूरी तेल सप्लाई वाले समुद्री रास्ते को खोलने की कोशिश से ईरान के साथ जंग लंबी खिंच सकती है। ट्रंप ने इस जंग को खत्म करने के लिए 4 से 6 हफ्ते का समय तय किया था, लेकिन इस मिशन की वजह से जंग इस समय से ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ट्रंप ने फैसला किया कि अमेरिका को ईरान की नेवी और मिसाइल स्टॉक को

कमजोर करने के अपने मुख्य मकसद को पाने पर ध्यान देना चाहिए। तेहरान पर स्ट्रेट के जरिए ट्रेड के फ्री फ्लो को फिर से शुरू करने के लिए डिप्लोमैटिक दबाव डालना चाहिए।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैसला लिया है कि अगर ये सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, तो व्हाइट हाउस यूरोपीय और गल्फ सहयोगियों पर इसे फिर से खोलने में आगे आने के लिए दबाव डालेगा। अधिकारियों ने आगे कहा कि सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर हैं, लेकिन वे राष्ट्रपि ट्रंप की तुरंत की प्राथमिकता नहीं हैं। हालांकि, इन आकलन के बावजूद, ईरान के साथ संघर्ष को लेकर ट्रंप का पब्लिक मैसेज एक जैसा नहीं रहा है।

सुबह, उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्दी डील नहीं हुई तो वह ईरान के सभी इलेक्ट्रिक प्लांट, तेल के कुओं और खार्ग आइलैंड को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस बीच, सरकार ने इस इलाके में अमेरिकी सेना की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। पिछले हफ्ते यूएसएस त्रिपोली और 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट इस इलाके में दाखिल हुई और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के कुछ हिस्से भी पहुंचने लगे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, 10,000 और जमीनी सैनिकों की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है।

वियतनाम की राजधानी में 2026 में अब तक कोविड-19 के 29 मामले सामने आए

एजेंसी

हनोई । वियतनाम की राजधानी हनोई में वर्ष की शुरुआत से अब तक कोविड-19 के 29 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि किसी के मौत की सूचना नहीं मिली है। हनोई सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि 20 से 27 मार्च के बीच 12 कम्यून और वार्ड में 17 नए कोविड-19 संक्रमण दर्ज किए गए, जबकि पिछले सप्ताह केवल तीन मामले सामने आए थे। बीए.3.2 वैरिएंट के संबंध में, जिसे वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने जनता से सावधान रहने के साथ घबराने से बचने की सलाह दी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यह वैरिएंट लैब स्थितियों में कुछ एंटीजनिक बदलाव और इम्यून एस्केप विशेषताएँ दिखाता है।

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से भीड़भाड़ वाले या बंद स्थानों में मास्क पहनने, नियमित सफाई और लक्षण बिगड़ने पर चिकित्सकीय देखभाल लेने जैसे बचाव उपाय बनाए रखने की सलाह दी। हाल ही में एक नया कोविड-19 वैरिएंट, जिसे अनौपचारिक रूप से 'सिकाडा' कहा गया है, कई क्षेत्रों में सीमित समूहों में पाया गया है, जिससे वैज्ञानिक इसके लक्षणों, संक्रामक क्षमता और संभावित प्रभाव की करीबी निगरानी कर रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, कोविड-19 एक संक्रामक रोग है, जिसे सार्स सीओवी-2 वायरस पैदा करता है।

इस वायरस से संक्रमित अधिकांश लोग हल्के से मध्यम श्वसन रोग का अनुभव करेंगे और बिना विशेष उपचार के ठीक हो जाएंगे। हालांकि, कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं और उन्हें चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

बुजुर्ग और हृदय रोग, मधुमेह, पुरानी श्वसन बीमारी या कैंसर जैसी पूर्व मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग गंभीर बीमारी विकसित होने की अधिक संभावना रखते हैं। किसी भी उम्र में कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो सकता है और गंभीर रूप से बीमार या मृत्यु के जोखिम में रह सकता है। संक्रमण को रोकने और धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका है रोग और वायरस के फैलाव के बारे में अच्छी जानकारी रखना। दूसरों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें, ठीक से फिट किया हुआ मास्क पहनें, हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड रब का नियमित उपयोग करें। जब आपकी बारी आए तो टीका लगवाएं और स्थानीय दिशानिर्देशों का पालन करें।

पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बहाल

एजेंसी

इस्लामाबाद। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाकिस्तान की मशहूर त्वचा विशेषज्ञ डॉ. फजीला अब्बासी की अंतरिम जमानत 100,000 रुपये के ज़मानती बॉन्ड पर बहाल कर दी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद आजम खान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने की। पीठ ने आगे की कार्यवाही के लिए उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश भी दिया। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान डॉ. फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में पेश हुईं। इस बीच अभिनेता हमजा अली अब्बासी ने साफ किया कि वह अपनी बहन के मामले में शामिल नहीं हैं। वकील नईम बुखारी ने दलील दी कि डॉ. फजीला तीन बार अदालत में पेश हुई थीं। एक बार वह पेश नहीं हो सकीं और तीन दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा किया, इसके बावजूद उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अंतरिम जमानत बहाल कर दी। उल्लेखनीय है कि संघीय जांच एजेंसी ने डॉ. फजीला अब्बासी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उनके 22 बैंक खातों में लगभग 25 अरब रुपये का टर्नओवर हुआ, जबकि उनकी घोषित सालाना आय केवल 400,000 रुपये से 600,000 रुपये के बीच थी।

गाजा में मानवीय मदद की कमी के कारण लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले बढ़ेः संयुक्त राष्ट्र

एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र । मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यकर्ताओं ने लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमलों में तेजी से बढ़ोतरी और गाजा पट्टी में मानवीय कामों में बढ़ती रुकावटों की ओर इशारा किया। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (ओसीएचए) ने कहा कि लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं, एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारियों पर हमले खतरनाक दर से बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अकेले वीकेंड में सात घटनाओं की रिपोर्ट दी, जिसमें ड्यूटी पर तैनात कम से कम नौ स्वास्थ्यकर्मी मारे गए। दक्षिणी लेबनान में ओसीएचए ने कहा कि हमलों में एम्बुलेंस को नुकसान हुआ, जिसमें नबातीह गवर्नरेट गवर्नरेट के कफर सर शहर में हुए हमले में घायल हुए लोगों को ले जा रही गाड़ियां भी शामिल हैं। ओसीएचए ने कहा कि जब से तनाव बढ़ना शुरू हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर 87 हमले हुए हैं, जिसमें 52 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए और 126 घायल हुए हैं। हफ्ते के अंत में जारी एक संयुक्त बयान में लेबनान के लिए यूएन के खास संयुक्त राष्ट्र के उप विशेष समन्वयक

और मानवीय समन्वयक इमरान रिजा और लेबनान में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि अब्दिनासिर अबुबकर ने स्वास्थ्यकर्मी और फर्स्ट रेस्पॉन्डर की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि मेडिकल स्टाफ और सुविधाओं को कभी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए।

लेबनानी अधिकारियों ने बताया कि वीकेंड में कम से कम 96 लोग मारे गए, जिससे तनाव बढ़ने के बाद से मरने वालों की कुल संख्या 1,238 हो गई, और 3,500 से ज्यादा घायल हुए।

ओसीएचए ने कहा कि बिगड़ते सुरक्षा हालात के बावजूद, ऑफिस और उसके पार्टनर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ और स्वास्थ्य साझेदार ने बेघर लोगों को 33,500 से ज्यादा मेडिकल सलाह दी है और 22,500 से ज्यादा लोगों को जरूरी दवाइयां पहुंचाई हैं। ओसीएचए ने कहा कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों में आम लोगों पर जानलेवा हमले जारी हैं। मानवीय मदद के कामों पर पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। गाजा के रिहायशी इलाकों में हवाई हमले और गोलाबारी हुई। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ने सोमवार को कहा कि वे इजरायली हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अपील याचिका फाइल करने पर विचार कर रहे हैं। इस याचिका में इजरायल के नए एनजीओ रजिस्ट्रेशन सिस्टम को चुनौती दी जाएगी। उनका कहना है कि यह सिस्टम इजरायल और कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में उनके काम करने की काबिलियत को और कम करता है। ओसीएचए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एनजीओ मानवीय मदद में अहम भूमिका निभाते हैं, जो मिलकर इन इलाकों में हर साल लगभग 1 बिलियन डॉलर की मदद देते हैं। नई रजिस्ट्रेशन जरूरतें उन कई तरीकों में से हैं जो लोगों की मानवीय सेवाओं तक पहुंच को कमजोर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ने इजरायली अधिकारियों से मानवीय राहत को तेजी से और बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में मदद करने, मानवीय कामों में रुकावट डालने वाली नीतियों को बदलने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओसीएचए ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मानवीय संगठन मानवीय सिद्धांतों के हिसाब से काम कर सकें।

page 1 and 8 Apr 2_page 1 Mar 25 final ds.qxd 4/1/2026 10:29 PM Page 2

स्थानीय समाचार

सीआईके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने के लिए पति-पत्नी के खिलाफ आरोपपत्र किया दायर

श्रीनगर, 01 अप्रैल (हि.स.)। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने बुधवार को तथ्यों में हेरफेर करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग करने के लिए पति-पत्नी की जोड़ी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 62(2) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूए (पी)) की धारा 13, 38, 39 के तहत पुलिस स्टेशन सीआईके श्रीनगर में दर्ज एफआईआर संख्या 05/2025 के संबंध में डॉ उमर फारूक भट और उनकी पत्नी शहजादा अख्तर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। बयान में कहा गया है कि मामला विश्वसनीय और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था जिसमें बताया गया था कि आरोपी शहजादा अख्तर ने सदस्यों के साथ एक सुनियोजित आपराधिक साजिश रची थी। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत और अपने पति डॉ उमर फारूक भट के साथ सक्रिय मिलीभगत से, कश्मीर की स्थिति के बारे में जानबूझकर झूठे, मनगढ़ंत और विकृत आख्यानों के निर्माण और प्रसार में शामिल थी।

जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति, प्रतिबंधित संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर, तथ्यों में हेरफेर करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन सहित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग में लगे हुए थे। उनके द्वारा प्रसारित सामग्री का उद्देश्य अलगाववादी और अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देना था जिससे भारत संघ के खिलाफ असंतोष, नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा मिलता था।

इसमें कहा गया है कि आगे की जांच से पता चला है कि आरोपी युवाओं को भड़काने और कट्टरपंथी बनाने, हिंसा भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के जानबूझकर इरादे से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य और आपराधिक दुर्भावना पैदा करने वाली सामग्री अपलोड करने और प्रसारित करने में भी शामिल थे। इस तरह की गतिविधियों ने शांति, शांति और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

जांच के समापन पर इसकी पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूत एकत्र किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन में दोनों आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता है। इसमें कहा गया है कि तदनुसार न्यायिक निर्धारण के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है।

बिलावर थाना में क्राइम रिव्यू बैठक, गुणवत्तापूर्ण जांच व त्वरित निस्तारण पर दिया जोर

कठुआ, 01 अप्रैल (हि.स.)। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने पुलिस थाना बिलावर में क्राइम रिव्यू बैठक की अध्यक्षता कर कानून-व्यवस्था की स्थिति और चल रही जांचों की प्रगति का जायजा लिया।

बैठक में लंबित मामलों, निस्तारण दर और जांच अधिकारियों के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। एसएसपी ने जघन्य एवं संवेदनशील मामलों की जांच में तेजी लाने, समय पर चार्जशीट

दाखिल करने और दोष सिद्धि दर बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सक्रिय पुलिसिंग, गश्त बढ़ाने और आम जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। साथ ही नशा तस्करों, अवैध खनन और अन्य असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में अपराध रोकथाम उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन और जन शिकायतों के त्वरित निपटारे पर भी फोकस किया गया। अधिकारियों को जनता के प्रति मित्रवत व्यवहार अपनाने तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एएसपी अपर कठुआ, एसडीपीओ बिलावर, सीनियर पीओ डीपीओ कठुआ, एसएचओ सहित पुलिस थाना बिलावर का स्टाफ मौजूद रहा।

हीरानगर में पंचायत मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा, पात्र मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर

कठुआ, 01 अप्रैल (हि.स.)। उप मंडल मजिस्ट्रेट एवं निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी हीरानगर फुलैल सिंह की अध्यक्षता में पंचायत निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में हीरानगर, मढ़हीन और डिंगा अंब के बीडीओ एवं एईआरओ ने भाग लिया, जबकि पंचायत बूथ स्तर के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

बैठक के दौरान एसडीएम ने 01 अप्रैल 2026 तक पात्र हुए सभी नागरिकों का अधिकतम पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार, अपात्र नामों को हटाने और मतदाताओं के स्थानांतरण से जुड़े मामलों के समयबद्ध निपटारे पर विशेष जोर दिया गया।

एईआरओ को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रक्रिया की निगरानी कर समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे पंचायत मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाएं और विवरण की जांच करें।

विशेष कैंप दिवसों के दौरान संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचकर ऑन-द-स्पॉट सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

उन्नत टमाटर उत्पादन हेतु फसल प्रबंधन एवं देखभाल

जम्मू संभाग के गर्म मैदानी क्षेत्रों में टमाटर फसल की रोपाई हो चुकी है और फसल में टमाटर उत्पादन भी आरम्भ हो गया है। अब आवश्यकता है इन्हें रोग और कीट मुक्त रखने की, समय समय पर सिंचाई की, भूमि की उर्वरता बनाए रखने की, समय पर फल तुड़ाई और बाजार में बिक्री की।

ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में यह समय टमाटर की पौध की रोपाई का काम पूरा करने का है। आइए, एक नजर डालें उन्नत टमाटर उत्पादन के लिए फसल प्रबंधन एवं देख भाल के कुछ आवश्यक पहलुओं पर-

आदर्श तापमान

टमाटर की फसल पाला नहीं सहन कर सकती है। इसकी खेती हेतु आदर्श तापमान 18. से 27 डिग्री से.ग्रे. है। 21-24 डिग्री से.ग्रे तापक्रम पर टमाटर में लाल रंग सबसे अच्छा विकसित होता है। इन्हीं सब कारणों से गर्म मैदानी क्षेत्रों में उत्पादि सर्दियों में, और ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में उत्पादित फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं। तापमान 38 डिग्री से.ग्रे से अधिक होने पर अपरिपक्व फल एवं फूल गिर जाते हैं।

भूमि

उचित जल निकास वाली बलुई दोमट भूमि जिसमे पर्याप्त मात्रा मे जीवांश उपलब्ध हो।

टमाटर की किस्में

देसी किस्म-पूसा रूबी, पूसा-120,पूसा शीतल, पूसा गौरव, अर्का सौरभ, अर्का विकास, सोनाली

संकर किस्म-पूसा हाइब्रिड-1, पूसा हाइब्रिड -2, पूसा हाइब्रिड-4, अविनाश-2, रश्मि तथा निजी क्षेत्र से शक्तिमान, रेड गोल्ड, 501, 2535 उत्सव, अविनाश, चमत्कार, यू.एस.440 आदि।

बीज की मात्रा और बुवाई बीजदर

एक हेक्टयेर क्षेत्र में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु लगभग 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 150-200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है।

वर्षा ऋतु के लिये जून-जुलाई तथा शीत ऋतु के लिये जनवरी-फरवरी। फसल पाले रहित क्षेत्रों में उगायी जानी चाहिए या इसकी पाले से समुचित रक्षा करनी चाहिए।

बुवाई पूर्व, थाइरम/मेटालाक्सिल से बीजोपचार करें ताकि अंकुरण पूर्व फफून्द का आक्रमण रोका जा सके।

नर्सरी मे बुवाई हेतु 1ङ्ग 3 मी. की ऊठी हुई क्यारियां बनाकर फॉर्मल्डिहाइड द्वारा स्टरलाइजेशन कर लें अथवा कार्बोफ्यूरान 30 ग्राम प्रति वर्गमीटर के हिसाब से मिलावें।

बीजों को बीज कार्बेन्डाजिम/ट्राइकोडर्मा प्रति किग्रा. बीज की दर से उपचारित कर 5 से.मी. की दूरी रखते हुये कतारों में बीजों की बुवाई करें। बीज बोने के बाद गोबर की खाद या मिट् टी ढक दें और हजारे से छिड़काव -बीज उगने के बाद डायथेन एम-45/मेटालाक्सिल से छिड़काव 8-10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए।

25 से 30 दिन का रोपा खेतों में रोपाई से पूर्व कार्बेन्डिजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल में पौधों की जड़ों को 20-25 मिनट उपचारित करने के बाद ही पौधों की रोपाई करें। पौध को उचित खेत में 75 से.मी. की कतार की दूरी रखते हुये 60 से.मी के फासले पर पौधों की रोपाई करें।

मेड़ों पर चारों तरफ गेंदा की रोपाई करें। फूल खिलने की अवस्था में फल भेदक कीट टमाटर की फसल में कम जबकि गेदें की फलियों/फूलों में अधिक अंडा देते हैं।

उर्वरक का प्रयोग

20 से 25 मैट्रिक टन गोबर की खाद एवं 200 किलो नत्रजन,100 किलो फॉस्फोरस व 100 किलो पोटाश। बोरेक्स की कमी हो वहॉ बोरेक्स 0.3 प्रतिशत का छिड़काव करने से फल अधिक लगते हैं।

सिंचाई

सर्दियों में 10-15 दिन के अन्तराल से एवं गर्मियों में 6-7 दिन के अन्तराल से हल्का पानी देते रहें। अगर संभव हो सके तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इर्रीगेशन द्वारा करनी चाहिए।

मिट् टी चढ़ाना व पौधों को सहारा देना (स्टेकिंग)

टमाटर मे फूल आने के समय पौधों में मिट् टी चढ़ाना एवं सहारा देना आवश्यक होता है। टमाटर की लम्बी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट् टी एवं पानी के सम्पर्क मे नही आ पाते जिससे फल सड़ने की समस्या नही होती है। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडों में विभिन्न ऊँचाईयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सुतली बांधते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेकिंग कहा जाता है।

खरपतवार नियंत्रण

आवश्यकतानुसार फसलों की निराई-गुड़ाई करें। फूल और फल बनने की अवस्था मे निंदाई-गुड़ाई नही करनी चाहिए।

रासायनिक दवा के रूप मे खेत तैयार करते समय फ्लूक्लोरेलिन (बासालिन) या रोपाई के 7 दिन के अंदर पेन्डीमिथेलिन से छिड़काव करें।

प्रमुख कीट एवं रोग

प्रमुख कीट- हरा तैला, सफेद मक्खी, फल छेदक कीट एंव तम्बाकू की इल्ली

प्रमुख रोग-आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ, झुलसा या ब्लाइट, फल संडन

एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण

चाहे टमाटर की खेती गर्म मैदानी क्षेत्रों में हो या ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में,एकीकृत कीट एवं रोग नियंत्रण के सिद्धांत एक से ही हैं, जिनका पालन हर अवस्था में करना चाहिए।

गर्मी मैदानी क्षेत्रों में टमाटर पौध की रोपाई से पहले गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें।

पौधशाला की क्यारियॉ भूमि धरातल से ऊंची रखे एवं फोर्मेल्डिहाइड द्वारा स्टरलाइजेशन कर लें।

क्यारियों को मार्च अप्रैल माह मे पॉलीथीन शीट से ढके भू-तपन के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए।

गोबर की खाद मे ट्राइकोडर्मा मिलाकर क्यारी में मिट् टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए।

पौधशाला की मिट् टी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से बुवाई के 2-3 सप्ताह बाद छिड़काव करें।

पौध रोपण के समय पौध की जड़ों को कार्बेन्डाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल मे 10 मिनट तक डुबो कर रखें।

पौध रोपण के 15-20 दिन के अंतराल पर चेपा, सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के लिए 2 से 3 छिड़काव इमीडाक्लोप्रिड या एसीफेट के करें। माइट की उपस्थिति होने पर ओमाइट का छिड़काव करें।

फल भेदक इल्ली एवं तम्बाकू की इल्ली के लिए इन्डोक्साकार्ब या प्रोफेनोफॉस का छिड़काव ब्याधि के उपचार के लिए बीजोपचार, कार्बेन्डाजिम या मेन्कोजेब से करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग के लक्षण पाये जाने पर मेटालेक्सिल + मैन्कोजेब या ब्लाईटॉक्स का धोल बनाकर छिड़काव करें। चूर्णी फंफूद होने सल्फर धोल का छिड़काव करें।

फलों की तुड़ाई, उपज एवं विपणन

जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो उस अवस्था मे फलों की तुड़ाई करें तथा फलों की ग्रेडिंग कर कीट व व्याधि ग्रस्त फलों दागी फलों छोटे आकार के फलों को छाटकर अलग करें। ग्रेडिंग किये फलों को केरैट में भरकर अपने निकटतम सब्जी मण्डी या जिस मण्डी मे अच्छा टमाटर का भाव हो वहां ले जाकर बेचें। टमाटर की औसत उपज 400-500 क्विंटल/है. होती है तथा संकर टमाटर की उपज 700-800 क्विंटल/है. तक हो सकती है।

कद्दूवर्गीय सब्जियों में - समन्वित कीट एवं रोग प्रबंधन

कद्दूवर्गीय सब्जियों को मानव आहार का एक अभिन्न अंग माना गया है। एक आदमी को रोजाना 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए परन्तु भारत में इसका 1/9वां भाग ही मिल पाता है। कद्दूवर्गीय सब्जियों की उपलब्धता साल में आठ से दस महीने तक रहती है। इसका उपयोग सलाद रूप में (खीरा, ककड़ी), पकाकर सब्जी के रूप में (तोरई, करेला, परवल) मीठे फल के रूप में (तरबूज व खरबूजा) मिठाई बनाने में (पेठा, परवल, लौकी) अचार बनाने में (करेला) प्रयोग किया जाता है। इन सब्जियों में विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों, सूत्रकृमियों एवं खरपतवारों के कारण लगभग 30 प्रतिशत नुकसान होता है।

इस वर्ग की सब्जियों में लगने वाले प्रमुख कीट व रोग तथा उनका प्रबंधन निम्न प्रकार से है।

कद्दूवर्गीय सब्जियों के प्रमुख कीट

लालभृंग

यह चमकीले लाल रंग का कीट पौधे की पत्तियों को विशेषकर प्रारम्भिक अवस्था में खाकर छलनी जैसा बना देता है। ग्रसित पत्तियाँ फट जाती हैं तथा पौधों की बढ़वार रूक जाती है।

नियंत्रण

इस कीट द्वारा होने वाले नुकसान से बचने हेतु फसल की बुवाई नवम्बर में करें। खरपतवारों को नष्ट कर खेत को स्वच्छ रखें । मैलाथियान 5 प्रतिशत दवा 20-25 किग्रा प्रति हेक्टर भूमि में मिलायें। इसके लिए कार्बोरिल 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव प्रभावी रहता है।

कटवर्म

यह कीट नन्हें या उगने वाले पौधों के बीज पत्रों तथा पौधों के शीर्ष को काट देते है जिससे खेत में पौधों की संख्या कम हो जाती है।

नियंत्रण

ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर कीट की निष्क्रिय अवस्थाओं को नष्ट कर दें। इसके नियंत्रण के लिए बीजों की बुवाई के समय या पौध रोपाई के समय कार्बोफ्यूरॉन 3 जी 25 किग्रा. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूमि में मिलायें ।

ब्लीस्टर बीट

यह आकर्षक चमकीले रंग तथा बड़े आकार का भृंग है। इसके पंखों पर तीन काले व तीन पीले रंग की पट्टियाँ होती हैं। यह पुष्पीय कलियों व फूलों को खाकर नष्ट कर देते हैं।

नियंत्रण

खेत में इनकी संख्या कम होने पर इन्हें हाथ से पकड़कर नष्ट कर देते हैं। अधिक प्रकोप होने पर 0.2 प्रतिशत कार्बोरिल का छिड़काव करें।

लीफ माइनर

यह पत्तियों के ऊपरी भाग पर टेढे-मेढ़े भूरे रंग की सुरंग बना देते है।

नियंत्रण इसके नियंत्रण हेतु नीम के बीजों का सत 5 प्रतिशत या ट्रायोफॉस 0.5 प्रतिशत का तीन सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव करें।

फलमक्खी-

यह कद्दूवर्गीय सब्जी फसलों में फल पर आक्रमण करने वाला कीट है। इसके मैगट छोटे फलों में अधिक नुकसान करते है। इसके मैगट पर सीधा नियंत्रण संभव नहीं है परन्तु वयस्क नर मक्खियों की संख्या पर नियंत्रण करने इनके प्रकोप को कम किया जा सकता है।

नियंत्रण

इसके नियंत्रण हेतु रात के समय खेत में प्रकाश पाश लगायें तथा नर वयस्कों को फेरोमेन ट्रेप लगाकर नियंत्रित करें। थायोडॉन को 6 मिली प्रति लीटर 4-5 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कीट की निगरानी हेतु फसल में गंध पाश 2 प्रति एकड़ जमीन आवश्यकता अनुसार लगायें।

चैंपा

ये छोटे आकार के काले एवं गहरे हरे रंग के कीट होते हैं। ये कोमल पत्तियों व पुष्पकलिकाओं का रस चूसते हैं। यह कीट वायरस जनित बीमारियों के वाहक का कार्य करता है।

नियंत्रण

इसके नियंत्रण हेतु डाइमिथिएट या फॉस्फोमिडॉन 0.5 प्रतिशत के घोल का 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें।

लाल मकड़ी

यह कीट भूरा, हल्का लाल रंग का होता है। जो पत्तियों की निचली सतह पर उत्तकों को खाकर जालीनुमा बना देता हैं। पर्णहरित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होता है। फलस्वरूप उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

नियंत्रण

लाल मकड़ी के नियंत्रण हेतु डाईकोफॉल 18.5 ईसी. 2.5 मिली दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

जड़ गांठ सूत्रकृमि

यह पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। प्रभावित पौधा कमजोर होकर पीला पड़ जाता है तथा पौधे का विकास अवरूद्ध होकर फलन नहीं हो पाता है।

नियंत्रण

लम्बे समय तक फसल चक्र अपनायें। मई-जून माह में खेत की गहरी जुताई कर खुला छोड़ दें। नेमागॉन अथवा कार्बोफ्यूरॉन 3जी 25 किग्रा प्रति हेक्टर बुवाई पूर्व भूमि में मिला दें।

कद्दूवर्गीय सब्जियों की प्रमुख व्याधियाँ रोग

फ्यूजेरियम उखटा

यह रोग एक मृदा जनित फफूंद फ्यूजेरियम स्पीसीज से होता है। इससे प्रभावित पौधा मुरझाकर सूख जाता है। पौधे की जड़ें व भीतरी भाग भूरा हो जाता है तथा पौधे की वृद्धि रूक जाती है। स्पष्ट लक्षण फूल आने व फल बनने की अवस्था में दिखाई देते है।

रोकथाम

- रोगरोधी किस्मों की बुवाई करें।
- भूमि सौर्यीकरण करने पर भी बीमारी को कम कर सकते है।
- बुवाई से पूर्व बीज के बाविस्टीन (1-2 किग्रा) से उपचारित करें तथा बीमारी आने के बाद ड्रेचिंग भी करें।

श्यामवर्ण (एन्थ्रेक्नोज)

यह रोग एक प्रकार की फफूंद कोलेटोट्राईकम लेजीनेरम से होता है। यह रोग तरबूजा, कद्दू में अधिक होता है जबकि पेठा में भी यह रोग अधिक होता है। यह रोग गर्म व आर्द्र मौसम में अधिक फैलता है तथा पौधे की किसी भी वृद्धि अवस्था में आ सकता है। पुरानी पत्तियों पर छोटे जलयुक्त या पीले धब्बे बनते है। ये धब्बे कोणीय अथवा गोलाकार हो सकते है बाद में ये आपस में मिल जाते है तथा सूख जाते है। पत्ती का यह सूखा भाग झड़ जाता है। खीरा, खरबूजा, लौकी की पत्तियों पर कोणीय या खुरदरे गोल धब्बे दिखाई देते हैं जो पत्ती के बड़े भाग या पूरी पत्ती को झुलसा देते है।

रोकथाम

- कद्दूवर्गीय जंगली पौधों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें।
- बीज को थाइरम या बाविस्टीन 2 ग्राम प्रतिकिग्रा बीज से उपचारित करके बोयें।
- मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से सात दिन के अंतराल पर दो बार छिड़कें।

चूर्णिल आसिता

इस रोग में पत्ती की ऊपरी सतह पर सफेद या धुधंले धूसर रंग के छोटे-छोटे धब्बे बनते हैं। जो बाद में पूरी पत्ती पर फैल जाते हैं। पत्तियों व फलों का आकार छोटा व विकृत हो जाता है व पौधों की पत्तियां असमय गिर जाती है।

रोकथाम

- रोगग्रसित पादप अवशेषों को नष्ट कर दें।
- रोग की प्रारम्भिक अवस्था में कैराथेन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

पत्ती झुलसा

सर्वप्रथम पत्ती पर हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में गहरे रंग के व आकार में बड़े हो जोते हैं। पत्तियों पर धब्बे केन्द्रीयकृत गोलाकार में बनते है। जिससे पत्तियाँ झुलसी हुई दिखाई देती हैं।

रोकथाम

- स्वस्थ बीज प्रयोग करें।
- फसल चक्र अपनायें।
- फसल पर इंडोफिल एम-45, 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करें।

कुकुम्बर मोजेक

पौधे छोटे रह जाते हैं। तथा ग्रसित पौधों की नयी पत्तियाँ छोटी आकार की तथा पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियाँ सिकुड़कर मुड़ जाती है। तथा पीले रंग का मोजेक क्रम दिखाई देता है। जिन्हें क्लारोटिक पेचेंज कहते है। कुछ फूल गुच्छे में दिखाई देते है। फल छोटे व विकृत हो जाते है या फलन बिल्कुल नहीं होता है।

रोकथाम

- उपचारित बीज ही बुवाई हेतु प्रयोग करें।
- रोगग्रस्त पौधों व जंगली खरपतवारों को उखाड़कर जला दें।
- इमिडाक्लोप्रिड (3-5 मि.ली./15 लीटर पानी) दवा का एक सप्ताह के अंतराल पर खड़ी फसल पर दो बार छिड़काव करें जिससे वाहक नष्ट हो जायें।

मृदुरोमिल आसिता

इस रोग में पत्ती की ऊपरी सतह पर हल्के कोणीय धब्बे दिखाई देते है तथा पत्ती की निचली सतह पर मृदुरोमिल फफूंद बैंगनी रंग की दिखाई देती है। फल आकार में छोटे हो जाते हैं तथा रोगी पौधे के पीले धब्बे जल्द ही लाल भूरे रंग के हो जाते हैं।

रोकथाम

- रोग रोधी किस्मों की बुवाई करें।
- फसल पकने के बाद फसल अवशेषों को जला दें।
- खड़ी फसल पर मैंकोजेब 0.2 प्रतिशत की दर से छिड़काव करें।

पत्तियों की शिराओं पर नेक्रोसिस धारियां बन जाती है। पर्व छोटे रह जाते है। उत्तकक्षय हो जाने से कलिका सूख जाती है। धीरे-धीरे कलिका वाली पूरी शाखा सूखने लगती है। पत्तियाँ सिकुड़कर पीली पड़ जाती है।

रोकथाम

- रोगग्रस्त पादपों को उखाड़कर जला दें।
- स्वस्थ बीजों को बोयें।
- इमिडाक्लाप्रिड 3-5 मिली. प्रति 15 लीटर पानी की दर से दो बार छिड़काव करें।
- खेत के चारों ओर बाजरा की फसल उगायें इससे रोग कम आता है।

- Compiled by: C M Sharma